पाक्षिक

क्रांतिरथ छत्तीसगढ़

सामाजिक क्रांति के पथ पर अग्रसर

शिवरतन शर्मा के प्रयास से ग्रामीण क्षेत्र में एक करोड़ रूपयें की लागत से 18 गांवों में बनेंगे रंगमंच और सामुदायिक भवन

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बयान की चर्चा तेज, प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल

◆ वर्ष - 22 ◆ अंक - 23 ◆ रायपुर 05 जून 2026 ◆ पृष्ठ - 08 ◆ मूल्य-5/- रुपया

एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी से लोगों को लगा झटका

रायपुर/दिल्ली। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तेल कंपनियों ने भारी बढ़ोतरी की है। नई दरों के अनुसार, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपये महंगा होकर अब 3113.50 रुपये का हो गया है। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 53.50 रुपये बढ़कर 3255.50 रुपये पहुंच गई है। ये बदलाव 1 जून यानी सोमवार से प्रभावी हो गया है, जिससे होटल, रेस्तरां, ढाबा और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। हालांकि, घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। व्यावसायिक इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की दरों में महानगरों के अंदर अलग-अलग बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में जहां प्रति सिलेंडर 42 रुपये ज्यादा देने होंगे। वहीं, कोलकाता के व्यापारियों पर 53.50 रुपये का ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिससे दोनों शहरों में कमर्शियल एलपीजी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा तेल विपणन कंपनियों ने छोटे व्यापारियों और नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपये का इजाफा किया है, जिसके बाद दिल्ली में ये छोटा सिलेंडर अब 821.50 रुपये की नई दर पर मिलेगा। राहत की एकमात्र बात ये है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले चौदह दशमलव दो किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

अमराई की परंपरा पुनर्जीवित करने की जरूरत

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का समापन करते हुए सांसद रायपुर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में आम को बहुत पवित्र माना गया है। भारतीय जनमानस में आम का एक विशिष्ट स्थान है आम के फल से लेकर पत्ते और लकड़ी तक का धार्मिक अनुष्ठानों और रीति-रिवाजों में बड़ा महत्व है। पहले हर गांव में जन सहयोग से अमराई (आम का बगीचा) लगाने की परंपरा थी जो समय के साथ-साथ धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि गांवों में अमराई लगाने की परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

समाज, संगठन और योग के प्रति समर्पित था रूपनारायण सिन्हा जी का जीवन - मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय रूपनारायण सिन्हा को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय रूपनारायण सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिन्हा का संपूर्ण जीवन समाजसेवा, संगठन निर्माण और योग के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित रहा। उनका निधन न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय रूपनारायण सिन्हा एक कुशल संगठनकर्ता, सरल, सौम्य और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने व्यवहार, कार्यशैली और समर्पण से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विशेष पहचान बनाई थी। योग के प्रति उनकी निष्ठा और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें विशिष्ट बनाती थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद श्री सिन्हा ने पूरे समर्पण और ऊर्जा के साथ योग आंदोलन को नई दिशा देने का कार्य किया। उन्होंने योग को केवल स्वास्थ्य का माध्यम नहीं, बल्कि जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिए अनेक नवाचार किए। उनके प्रयासों से प्रदेश में योग गतिविधियों को नई पहचान और व्यापक जनस्वीकृति मिली।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय श्री सिन्हा के साथ बिताए गए क्षणों को स्मरण करते हुए कहा कि उनसे नियमित मुलाकात होती थी और हर मुलाकात में वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए योग आधारित नए विचार साझा करते थे। उनकी सोच सदैव रचनात्मक और जनहितकारी होती थी। वे योग को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर सक्रि य रहते थे और इसी उद्देश्य को अपने जीवन का मिशन बना चुके थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष जशपुर के रणजीता स्टेडियम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्र म की सफलता में श्री सिन्हा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। सीमित समय में उन्होंने जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ उस आयोजन को भव्य स्वरूप दिया, वह उनकी संगठन क्षमता और कार्यकुशलता

का उत्कृष्ट उदाहरण है। उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता ने योग के प्रति जनजागरूकता को नई ऊंचाई प्रदान की थी। उनका जीवन समाज के प्रति समर्पण, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक था, जो आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा देता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

श्रद्धांजलि सभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, विधायक श्री अमर अग्रवाल, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, विधायक श्री अजय चंद्राकर, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, श्री रमेश बैस, श्री राम प्रताप, श्री पवन साय, डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना, श्री राम दत्त, श्री राजीव लोचन महाराज सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, योग साधक एवं योग जगत से जुड़े लोगों ने उपस्थित होकर स्वर्गीय रूपनारायण सिन्हा को श्रद्धासुमन अर्पित किया।

सुशासन, विकास और जनकल्याण हमारी सरकार की पहचान - मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुशासन, विकास और जनकल्याण राज्य सरकार की कार्यशैली और पहचान है। सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री श्री साय आज सुशासन तिहार के अंतर्गत हेमूनगर में आयोजित जिला स्तरीय समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 134 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी की तथा आमजनों के हित में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में 80 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की। ट्राईसाइकिल प्राप्त कर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनशील नीतियों का उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास की चाबियां भी सौंपीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने एसईसीएल के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मद से 22 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 200 सीटर बहुउद्देशीय वृद्धाश्रम भवन का शिलान्यास किया। इस भवन में वरिष्ठ नागरिकों को प्राकृतिक चिकित्सा, योग, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी तथा समग्र पुनर्वास जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि वृद्धजन समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनके सम्मानजनक जीवन के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने 18 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से बनने वाले 500 सीटर दिव्यांगजन शिक्षण-प्रशिक्षण एवं बहुउद्देशीय पुनर्वास केंद्र का शिलान्यास किया। यह केंद्र दिव्यांगजनों को शिक्षा, कौशल विकास, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑडिटरी ट्रेनिंग तथा पुनर्वास की समग्र सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इससे दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बनेंगे और रोजगार तथा स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय में लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से स्थापित अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि इससे गंभीर एवं जटिल बीमारियों की जांच स्थानीय स्तर पर संभव हो सकेगी और मरीजों को बेहतर, त्वरित तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सुशासन तिहार केवल एक अभियान नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, सुरक्षा बलों के पराक्रम और बस्तर की जनता के सहयोग से नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता प्राप्त हो रही है। बस्तर में अब सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है।

मंत्री वर्मा ने दी 55 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

विकास कार्यों में नहीं होगी कोई कमी -राजस्व मंत्री वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश की जनता की समस्याओं के त्वरित और मौके पर ही निराकरण के लिए 'सुशासन तिहार' के तहत समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम छेरकापुर में एक विशाल समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्र म में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ?शिविर के दौरान राजस्व मंत्री वर्मा ने क्षेत्र के विकास को गति देते हुए 55 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। साथ ही, विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री और प्रमाण पत्र वितरित किए। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य शासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच सीधे पहुंचकर शासकीय योजनाओं का फीडबैक लेना और समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। हमारा प्रयास है कि युवा, गरीब, बच्चे और किसान,समाज का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्यधारा से जुड़े।

मिलीं प्रमुख विकास सौगातें

क्षेत्र के अधोसंरचना विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं मंत्री ने कीं। उन्होंने सेमरिया में सीसी रोड निर्माण के लिए 30 लाख रुपये और गोड़ा सरस्वती शिशु मंदिर के विकास हेतु 12 लाख रुपये की स्वीकृति दी। इसके साथ ही, छेरकापुर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, छेरकापुर में मुक्तिधाम निर्माण और सीसी रोड निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य आम जनता की तकलीफों का जमीनी स्तर पर समाधान करना है। 'विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी' के तहत राज्य सरकार समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से शासन-प्रशासन सीधे जनता के द्वार तक पहुँच रहा है।

68.54 लाख महिलाओं के खातों में अंतरित हुए 642.27 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री साय ने जारी की महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68 लाख 54 हजार महिलाओं के बैंक खातों में 642 करोड़ 27 लाख 77 हजार 950 रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा महतारी वंदन योजना इस दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल के रूप में सामने आई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसी भी समाज और राज्य की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती, जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से सम्मानित न किया जाए। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश की माताओं और बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 1 मार्च 2024 से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना से प्राप्त राशि का उपयोग महिलाएं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण तथा छोटे-छोटे स्वरोजगार कार्यों में कर रही हैं। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ महिलाओं की सामाजिक भागीदारी भी बढ़ी है।

जून 2026 में जारी 28वीं किस्त के साथ ही योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश की महिलाओं को कुल 18 हजार 165 करोड़ 19 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। यह राशि महिलाओं के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के अनुरूप सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर में संचालित नियद नेल्लानार अभियान के माध्यम से 7 हजार 770 नई महिलाओं को महतारी वंदन योजना से जोड़ा गया है। इससे दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों की महिलाओं को भी आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना आज केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान, विश्वास और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक बन चुकी है। योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार तथा समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

गाँव के द्वार पहुँची डिजिटल सरकार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत बड़ेकनेरा में स्थापित अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का निरीक्षण कर ग्रामीण डिजिटल सुशासन के अभिनव मॉडल 'सेवा सेतु' की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद कर योजनाओं की पहुंच, पारदर्शिता और प्रभाव के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को उनके गांव में ही सहज, सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि 'सेवा सेतु' अभियान और अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं, जिनसे आमजन को सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर लगाने से मुक्ति मिल रही है। मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान ग्राम की हितग्राही श्रीमती कौशल्या मानिकपुरी ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से महतारी वंदन योजना की राशि प्राप्त हो रही है।

संक्षिप्त समाचार

चाकू लहराते हुए युवक को पुलिस ने दबोचा

भाटापारा । पुलिस प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों के विरूद्ध चलाये जा रहे धर पकड़ अभियान में लाल बहादुर शास्त्री वार्ड पटपर चौक में आने जाने वाले लोगो को चाकू दिखाकर भयभीत करने वाले जय कुमार उर्फ जेला निर्मलकर मूल निवासी बजरंग वार्ड को घेराबंदी कर चाकू के साथ धर दबोचा है। पुलिस ने जय कुमार निर्मलकर के खिलाफ 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर रिमांड पर जेज दिया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम की कार्यवाही , 2 किलो खराब मोमोस किया नष्ट

भाटापारा। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता जांच की जा रही है। इसी कड़ी में शहर के कई दुकानों का निरीक्षण किया गया और खराब मोमोस व चटनी को नष्ट कराया गया। शहर में त्रिपुरा सुंदरा देवी मोमोस सेंटर, डबल बहादुर मोमोस सेंटर,जय हिन्द हॉटल के पास सदर बाजार, पशुपति नाथ मोमोस एण्ड चाईनीस सेंटर की जाँच कर त्रिपुरा सुंदरा देवी मोमोस सेंटर में 2 किलोग्राम खराब मोमोस व डबल बहादुर मोमोस सेंटर में 1 किलोग्राम खराब मोमोस चटनी नष्ट कराया गया। उक्त फर्मों से जाँच हेतु मोमोस चटनी, स्टिम्ड वेज मोमोस, चाईनीज पकौड़ा, फाई वेज मोमोस एवं फिंगर चिप्स का नमूना लेकर जाँच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला जेजा गया। मोमोस एवं चाईनीज पकौड़ा फर्मों को खाद्य सुरक्षा एवं मानकचाईनीज पकौड़ा फर्मों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत साफ-सफाई के सुधारात्मक निर्देश दिए गये।

अवैध कब्जा करने होड़ मची है शहर व ग्रामीण क्षेत्र में

भाटापारा। शहर में एक लंबे समय से अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर अभियान अब तक प्रारंभ नही किये जाने से अवैध कब्जा करने वालो के हौसले बुलंद है । शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा करने होड़ मची है। राजस्व प्रशासन , नजुल प्रशासन, रेल प्रशासन , कृषि उपज मंडी , लोक निर्माण विभाग सहित पालिका प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से अवैध कब्जा हटाओं अभियान चलाकर जनहित में बहुमुल्य शासकीय जमीन , तालाब , गौठान , खेल मैदान व शमशान भूमि को बचाने के लिए प्रयास किये जाने की दरकार है। मौजुदा समय में सबसे अधिक अवैध कब्जा व अवैध निर्माण गुरूनानक वार्ड स्थित पंचशील नगर व टेहका भाठा में हो रहा है। जहां औसतन अवैध कब्जे से दो मकान रोज अवैध रूप से बन रहे है। इसी तरह मुंशी स्माई वार्ड बायपास नहर के किनारे भी बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हो रहे है । अवैध कब्जे करने वाले शहर के भीतर शहर थाना से लेकर गोविंद चौक सदर बाजार पंचायती मंदिर , जैन मंदिर सती मंदिर , कॉलेज मार्ग होकर ग्राम खोलवा तक धड़ल्ले से हो रहे है । खोलवा गांव के मुख्य मार्ग पर तो कच्ची लिखापढ़ी से जगह की खरीदी बिक्री कर मुख्य मार्ग के किनारे ही अवैध निर्माण कार्य किये जा रहे है। कुछ लोगो ने तो रहवासी मकान व दुकान तान लिये है । इसी प्रकार के हालात महत्वपूर्ण तालाब कल्याण सागर कईहा तालाब , पैठु डबरी में भी बने हुए है। जहां लोग कब्जा पर कब्जा बढ़ाकर अवैध कब्जा को बेखौफ ढंग से अंदाज दे रहे है। जबकि प्रशासनिक कार्यवाही इस दिशा में शुन्य है जिसके कारण अवैध कब्जा विकराल रूप ले रहा है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम सुरजपुरा , दतरेंगा , दतरेंगी , धौराभाठा सिद्धबाबा , खोखली , सेमरिया , कोढापार, मुढीपार ,खपराडीह , ढाबाडीह , पेन्ड्री ,टिकुलिया , सुमा , कैथी , टेहका ,तरेंगा , सुरखी सहित अन्य गांव में धड़ल्ले से सड़क किनारे अवैध कब्जे हो रहे हैजिसे रोकने में उस क्षेत्र के पटवारी व राजस्व अमला पुरी तरह विफल साबित हो रहा है। जनहित में जिला प्रशासन को भाटापारा शहर व ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जे को रोकने शीघ्र ही महाअभियान चलाना चाहिए ताकि करोड़ो रूपयें की बेशकीमती जमीन सुरक्षित रह सके ।

सट्टा पट्टी के साथ सटोरिये चढ़े पुलिस के हत्थे

भाटापारा। प्रभारी पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा सट्टा पट्टी के कारोबार में संलिप्त सटोरियों के विरूद्ध चलाये जा रहे धर पकड़ अभियान में सट्टा पट्टी का कारोबार करते हुए भाटापारा शहर के भगत सिंह वार्ड निवासी रवि पठारी जो कि मुंशी स्माईल वार्ड में सट्टा पट्टी का कारोबार कर रहा था उसे दबोचा गया है। इसी तरह संतोष बंजारे महासती वार्ड निवासी को भी सट्टा पट्टी के साथ पकड़ा गया है। पुलिस की संयुक्त टीम ने योगेन्द्र चतुर्वेदी , हरिशंकर घृतलहरे , गिरजा मारकण्डेय , खेलचंद यादव , इतवारीराम जांगड़े को भी सट्टा पट्टी के कारोबार करते पकड़ा है। उक्त सभी सटोरियों के कब्जे से पांच नग स्मार्ट फोन मोबाईल भारी मात्रा में सट्टा पट्टी व दाव लगाने की सामग्री के साथ साथ 10444 रूपयें नगद जब्त किया है । उक्त सभी लोगो के विरूद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 20,22 तथा धारा 6(क) के तहत कार्यवाही की गई है । उक्त कार्यवाही संयुक्त टीम द्वारा की गई ।

शिवरतन शर्मा के प्रयास से ग्रामीण क्षेत्र में एक करोड़ रूपये की लागत से 18 गांवों में बनेंगे रंगमंच और सामुदायिक भवन

ब्यूरोचीफ संतोष साहू

भाटापारा। वरिष्ठ भाजपा नेता शिवरतन शर्मा के अथक प्रयास से ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्ना विकास कार्यो के लिए एक करोड़ रूपयें से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा देते हुए प्रभारी मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने भाटापारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत शिवरतन शर्मा की अनुशंसा पर विधानसभा के लिए 01 करोड़ रुपये की लागत से 18 महत्वपूर्ण विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत कार्यों से भाटापारा और सिमगा विकासखंड के 18 ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीण सीधे तौरपर लाभान्वित होंगे। उक्त कार्यों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, सामाजिक आयोजनों के लिए स्थान उपलब्ध कराने और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत ग्राम जेथीडीह शिव मंदिर के पास , 5 लाख ,पाटन - 5 लाख, कडार - 4 लाख, लिमतरा - 5 लाख,मोपका - 5 लाख, मुसवाडीह/भोथीडीह 3 लाख,तुरमा - 5.50 लाख, मोपर - 4 लाख गुडेलिया अटल चौक एवं शहीद वीर नारायण चौक - 5 लाख चबूतरा व रंगमंच निर्माण के लिए स्वीकृत किये गये है इसी तरह सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए खोखली - 6.50 लाख, बिटकुली सतनामी पारा - 6.50 लाख, दतरेंगी जायसवाल पारा - 10 लाख, देवरानी यादव पारा - 5 लाख, रामपुर यादव पारा - 10 लाख, दरचुरा महामाया पारा - 6.50 लाख स्वीकृत किये गये है। इसी प्रकार शेड एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य हेतु ग्राम सुरखी आदिवासी पारा - 4 लाख शेड, तरेंगा शिशु मंदिर पास - 5 लाख अतिरिक्त कक्ष ,मल्दी शिशुमंदिर पास - 5 लाख अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए स्वीकृत किये गये है । उक्त कार्य स्वीकृति पर शिवरन शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के 'विकसित छत्तीसगढ़' के संकल्प को पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं।

उन्होंने प्रभारी मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के प्रति कार्य स्वीकृति पर आभार प्रकट किया । भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के भाटापारा व सिमगा क्षेत्र को विकास मद में करोड़ो रूपये की स्वीकृति पर शिवरतन शर्मा के प्रयास के लिए राकेश तिवारी सुनील गोलु यदु , महाबल बघेल , राजा कामनानी, मनीष मिश्रा, मनीष पंजवानी, पवन वर्मा , हेमसिंग चौहान ,मनेन्दर सिंग गुंबर , दिलीप छाबड़िया , सतीश तलरेजा सहित अन्य नेताओं ने बधाई दी है।

भीषण गर्मी को देखते हुए उपभोक्ताओं से धैर्य रखने और सहयोग बनाए रखने की डी.ई. ने की अपील

ब्यूरोचीफ संतोष साहू

भाटापारा। विद्युत विभाग के डीई व्ही के राठिया ने क्षेत्र की जनता से सहयोग की अपील की है । उन्होंने बताया कि प्रदेश में भीषण तपती गर्मी के साथ शहर का तापमान 44 सेंटीग्रेड के पार जा चुका है और रात में भी गर्म हवाओं के साथ लगभग तापमान 30 सेन्ट्रीग्रेड के आसपास हैं। जिसके चलते इस असहनीय माहौल में हर कोई अपने घरों में एसी और कूलर के सहारे राहत ढूंढ रहा है। वही बिजली की मांग भी इतिहास के पन्ने में शायद दर्ज होकर सारे रिकॉर्ड तोड़कर 7,000 मेगावाट के पार जा चुकी है। लेकिन इस संकट के बीच भी विद्युत विभाग अपना कार्य ईमानदारी से करते हुए आम उपजेक्ताओं को विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से देने में सफल हो रहा है।लेकिन उसके बावजूद भी इस तपती गर्मी के चलते मशीन ट्रांसफार्मर भी थक से गए है। 44 डिग्री की झुलसाती धूप में ये ट्रांसफॉर्मर और केबल बिना रुके, लगातार सुलग रहे हैं। जब क्षमता से अधिक लोड पड़ता है तो ये मशीनें भी 'हांफने' लगती हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी इस जानलेवा धूप में, सड़कों पर, खंजें पर चढ़कर सुलगते हुए ट्रांसफॉर्मरों और फॉल्ट वाले केबलों को ठीक कर रहे होते हैं। विभाग के कर्मचारियों से विवाद करने के बजाय, उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति और आदर रखें। श्री व्ही के राठिया ने कहा कि जिस कमरे में कोई न हो, वहां के एसी, कूलर और लाइट बंद कर देना चाहिए वही पीक आवर्स में दोपहर और रात के समय जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, तब भारी बिजली उपकरणों जैसे वॉशिंग मशीन, पानी का पंप, या ई-व्हीकल चार्जिंग का उपयोग भी कम से कम करने की सलाह विभागीय अधिकारियों ने दी है। बिजली कर्मियों के हौसले को बनाए रख उनका सहयोग करे।

मॉडर्न इंग्लिश स्कूल का परीक्षा परिणाम बेहतर होने पर लोगों ने खुशी जाहिर की

भाटापारा। स्थानीय मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में घोषित पांचवी और आठवीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिये गये है। जिसमें मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के आठवीं बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान सोनाली माईती, द्वितीय स्थान शुभम साहू और तृतीय स्थान मोहम्मद कैफ को मिला है।

इसी तरह कक्षा पांचवी में प्रथम स्थान क्रमशः जीविका साहू और विद्या देवांगन ने हासिल किया है। द्वितीय स्थान मनीष कुमार साहू और तृतीय स्थान अस्तित्व मिश्रा ने प्राप्त किया है। मॉडर्न स्कूल के उक्त उत्कृष्ट परिणाम पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए सभी सफल छात्र छात्राओं को स्कूल की प्राचार्या श्रीमती प्रीति ताम्हने एवं स्टाफ ने बधाई दी है।

भीषण गर्मी से परेशान बंदरों का कुनबा भाटापारा शहरी क्षेत्र पहुंचा

भाटापारा। शहर व क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी नेआम इंसान के साथ साथ मुक पशुओं पक्षी, जानवर व वन क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं को भी परेशान कर रखा है। भाटापारा क्षेत्र में नौतपा के दौरान लगातार पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है जिसके चलते गर्मी से जहां आम इंसान हलाकान है वहीं पानी व छाव की तलाश में बंदरों का पुरा कुनबा शहर के घरों के छत व कवेलुपोश मकान पर पहुंचने लगा है । चारा पानी की तलाश में बंदरों के झुंड में पहुंचने का क्रम शहर में लगातार जारी रहने से खपरा छानी मकान वाले ज्यादा परेशान है क्योकि उनकी छानी पर बंदर समुह में उछलकूद मचाकर खपरा को तोड़ रहे है वहीं बंदरों के उत्पात से अनेक घरों के खपरा छानी नीचे गिरने लगे है। बंदरों के झुंड में बंदर बंदरिया के अलावा छोटे छोटे उनके बच्चे भी है जो तेज गर्मी से व्याकुल होकर चारा पानी की तलाश में शहरों की ओर बड़ी तादाद में कूच कर रहे है वैसे भी तेज औद्योगिकरण के कारण अब जंगल सिमट रहें है इसलिए बंदरों का परिवार बड़ी संख्या में शहर के भीतर प्रवेश करने मजबुर है शहर के 11 किलोमीटर दुर मदकुद्वीप क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बंदर अठखेलियां करते अक्सर नजर आ जाते है और वे इन दिनों लंबा सफर तय करके भाटापारा शहरी क्षेत्र में पहुंच चुके है जिसे देख आम इंसान के छोटे छोटे बच्चे खुशी से रोमांचित हो रहे है वहीं खपरापोश घर वाले उन्हें खपरा टुटने के डर से भगाने लगे है । बहरहाल चिलचिलाती धुप से बचने भाटापारा शहर की ओर आये बंदरों की टोली को अनेक वन्यजीव प्रेमी बंदर परिवार को चना , गुड़ , केला , तरबुज , बिस्कुट के अलावा अन्य खाद्य सामग्री व पानी देकर मदद पहुंचा रहे है। शहर के भीतर केबल तार एवं विद्युत तार के मकड़जाल के रूप में फैले होने के कारण बंदरो को उछलकूद के दौरान कभी कभी अपने प्राण भी गवाने पड़ रहे है। कुल मिलाकर गर्मी की तपिश से आम इंसान के साथ साथ बंदर भी परेशान है ।

अवैध रेत भण्डारण पर प्रशासन की छापेमारी 88 ट्रेक्टर रेत जब्त

ब्यूरोचीफ संतोष साहू

भाटापारा। अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त टीम द्वारा रात्रिकालीन जांच व छापमारी की कार्यवाही भी लगातार की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार मंगलवार को राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा रात्रिकालीन छापेमारी में अवैध रूप से भण्डारण किये गये 88 ट्रेक्टर रेत जब्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम एवं एस डीओपी सिमगा के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा मंगलवार को ग्राम लिमतरा में रात्रिकालीन जांच के दौरान अवैध रेत डम्प पाया गया। पटवारी व सरपंच से जानकारी ली गई और सम्बंधित को मौके पर तलब कर पूछताछ की गई। रेत भण्डारण के समबंध में कोई दास्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित लगभग 88 ट्रेक्टर रेत को जब्त कर सरपंच के सुपुर्दगी में दिया गया। अवैध भण्डारित रेत में रामाकुमार रात्रे 17 ट्रेक्टर, परमेश्वर बघेल 8 ट्रेक्टर, तोरण निषाद 5 ट्रेक्टर, गुलाब दास 35 ट्रेक्टर, रामकुमार 18 ट्रेक्टर एवं अज्ञात व्यक्ति 5 ट्रेक्टर शामिल हैं। इसके साथ ही 2 ट्रेक्टर भी जब्त किया गया। इसी तरह तहसील पलारी में अवैध रेत परिवहन करते 2 ट्रेक्टर को जब्त कर थाना पलारी के सुपुर्द दिया गया

शिवरतन शर्मा की कार्यशैली से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवाओं ने भाजपा प्रवेश किया

ब्यूरोचीफ संतोष साहू

भाटापारा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रीति नीति एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के डबल इंजन सरकार की जनहितकारी योजनाओं से प्रभावित होकर तथा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता शिवरतन शर्मा की सक्रियता से प्रेरणा लेते हुए ग्राम कौशलपुर मंडल अंतर्गत गांव कोलिहा के 10 युवाओं ने स्वप्रेरित होकर भाटापारा भाजपा नेता के निवास पहुंचकर भाजपा प्रवेश किया। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता शिवरतन शर्मा ने सभी 10 युवाओं को भाजपा का गमछा पहनाकर आत्मीय अभिनंदन व स्वागत किया व कहा कि युवाओं के भाजपा प्रवेश से पार्टी और मजबुती से जनता के हित में कार्य करेगी। भाजपा प्रवेश करने वालों में रोशन साहू, रितेश साहू, अंशु बंजारे ,प्रियांशु पाटले , शेखर रावते, राकेश लहरे , दुर्गेश लहरे, मुकेश लहरे , रोशन डहरे, चेतन पाटले, लक्की पाटले सहित अन्य लोग शामिल है। उपस्थित लोगो को संक्षिप्त संबोधन में शिवरतन शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हो रहे बहुमुखी विकास को देखकर आज का युवा वर्ग बड़ी तादाद में भाजपा संगठन से जुड़ रहा है। महतारी वंदन योजना कृषक उन्नति योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं ने हर वर्ग को भाजपा का विश्वास जीतने में प्रेरित किया है। ग्राम कोलिहा के ऊर्जावान युवाओं के भाजपा प्रवेश से पार्टी और अधिक मजबुत होकर जनता हित में कार्य करेगी।

अवैध शराब के साथ कोचिया गिरफ्तार

भाटापारा। आमजनों की शिकायत एवं समस्याओं का त्वरित निराकरण करने हेतु जिले में महत्वाकांक्षी योजना समाधान सेल प्रारंभ किया गया है। पुलिस अधीक्षक ओ.पी.शर्मा के कुशल निर्देशन में समाधान सेल में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना भाटापारा शहर की पुलिस टीम द्वारा भाटापारा शहर में माल धक्का के पास घेराबंदी कर अवैध रूप से बिक्री करने के लिए शराब ले जाते हुए 01 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शराब कोचिया से 4900 कीमत मूल्य का 49 पाव देशी मसाला शराब एवं अवैध रूप से शराब परिवहन में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल क्र. सीजी22 एजे1608 जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना भाटापारा शहर में धारा 34(2) आबकारी के तहत अपराध पंजीबध्द कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई है।

पर्यावरणीय संकट से समाधान की ओर बढ़ने का समय

वर्तमान संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक संकट भी है। वायु प्रदूषण लाखों लोगों की असामयिक मृत्यु का कारण बन रहा है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मौसम चक्र असंतुलित हो गया है। गरीब और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य को बचाने का वैश्विक संकल्प है। वर्ष 2026 का विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है जब जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण, जल संकट, वायु प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पृथ्वी के अस्तित्व को गंभीर चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। इस वर्ष की थीम "प्लास्टिक प्रदूषण का अंत" (ठमंज च्सेंजपब च्वससनजपवद) केवल प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का आह्वान नहीं है, बल्कि उपभोगवादी जीवनशैली और प्रकृति-विरोधी विकास मॉडल पर पुनर्विचार का भी संदेश है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को झेल रही है। कहीं भीषण गर्मी जीवन को असहनीय बना रही है, कहीं अनियंत्रित वर्षा और बाढ़ तबाही ला रही है, तो कहीं सूखा और जल संकट मानव अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड के जंगलों में आग, हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, महानगरों में प्रदूषण, बेंगलुरु जैसे तकनीकी नगरों में जल संकट और लगातार बढ़ती गर्मी इस बात के संकेत हैं कि पर्यावरणीय संकट अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें चेतावनी दे रही हैं कि पिछले एक दशक में जलवायु संबंधी आपदाओं से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है और खरबों डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है। जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण-ये तीनों संकट परस्पर जुड़े हुए हैं। यदि वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया गया तो मानव सभ्यता के सामने अभूतपूर्व संकट खड़ा हो सकता है। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन आज भी दुनिया उस दिशा में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि विश्व के सामने उपस्थित इस सबसे बड़े संकट को भारत की राजनीति में वह महत्व नहीं मिला, जिसका वह अधिकारी है। चुनावी घोषणापत्रों में पर्यावरण का उल्लेख तो होता है, लेकिन वह केवल औपचारिकता भर रह जाता है। राजनीतिक दल यह मानकर चलते हैं कि पर्यावरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन वोट दिलाने वाले मुद्दे नहीं हैं। परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रश्न न तो चुनावी बहस का हिस्सा बनते हैं और न ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का। जबकि सच्चाई यह है कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा इसी प्रश्न पर निर्भर करती है।

पर्यावरणीय संकट का मूल कारण विकास की वह अवधारणा है जिसमें प्रकृति को केवल संसाधन और उपभोग की वस्तु मान लिया गया है। हमने जंगलों को उद्योगों के लिए, नदियों को अपशिष्ट के लिए और भूमि को कंक्रीट के जंगलों में बदलने के लिए प्रयोग किया। प्रकृति हमें जीवन का आधार निःशुल्क देती है, लेकिन हमने उसके प्रति कृतज्ञता के बजाय दोहन का व्यवहार अपनाया। परिणामस्वरूप वनस्पतियों का विनाश, वन्य जीवों का संकट, भूमिगत जल का क्षय और प्रदूषण का विस्तार निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय संस्कृति ने सदैव प्रकृति को पूजनीय माना है। वृक्षों, नदियों, पर्वतों और वनस्पतियों को केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवनदाता के रूप में देखा गया। आयुर्वेद और वनौषधि विज्ञान इसका श्रेष्ठ उदाहरण हैं। जड़ी-बूटियों और वनस्पतियों ने हजारों वर्षों तक मानव स्वास्थ्य की रक्षा की, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में यह ज्ञान और प्राकृतिक संपदा दोनों उपेक्षित होते गए। आज जब नई-नई बीमारियां मानव जीवन को चुनौती दे रही हैं, तब पुनः प्रकृति और वनस्पति जगत की ओर लौटने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

वर्तमान संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और नैतिक संकट भी है। वायु प्रदूषण लाखों लोगों की असामयिक मृत्यु का कारण बन रहा है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। कृषि व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मौसम चक्र असंतुलित हो गया है। गरीब और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कभी इंदिरा गांधी ने कहा था कि 'गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है।' आज यह कथन और अधिक प्रासंगिक हो गया है क्योंकि गरीबी और पर्यावरणीय विनाश एक-दूसरे को बढ़ाने वाले कारक बन गए हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनों की कमी नहीं है। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से लेकर अनेक पर्यावरणीय कानून बनाए गए। लेकिन कानूनों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच गहरी खाई बनी हुई है। अवैध खनन, वनों की कटाई, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अनदेखी और पर्यावरणीय मंजूरियों में शिथिलता इस बात का प्रमाण हैं कि संस्थागत इच्छाशक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी आशा की किरण दिखाई देती है। युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। विभिन्न सर्वेक्षणों में बड़ी संख्या में युवाओं ने जलवायु संकट को गंभीर विषय माना है और सरकार से इस संबंध में शिक्षा एवं जनजागरण की अपेक्षा की है। यह संकेत है कि नई पीढ़ी पर्यावरण को केवल प्रकृति का नहीं, बल्कि अपने भविष्य का प्रश्न मान रही है।

अतिथि संपादक - ललित गर्ग

विश्व पर्यावरण दिवस विशेष... एनएचएआई का पर्यावरण-हितैषी निर्माण पर जोर

फ्लाई-ऐश और औद्योगिक कचरे की रिसाइक्लिंग से बन रहीं पर्यावरण-अनुकूल सड़कें

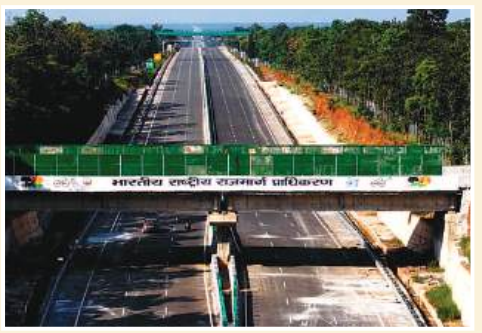

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने आधुनिक सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में कई अभिनव पहलें की हैं। प्रकृति, वन्य जीव और आधुनिकता के बीच बेहतरीन संतुलन स्थापित करने का यह अनूठा मॉडल विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की विभिन्न परियोजनाओं में धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। औद्योगिक कचरे के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देकर पर्यावरण-अनुकूल सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मील का पत्थर साबित हो रही हैं।

औद्योगिक कचरे की रिसाइक्लिंग से राजमार्गों का निर्माण

राजमार्ग निर्माण में थर्मल पावर प्लांट की फ्लाई-ऐश (राख) का उपयोग करके एनएचएआई ने पर्यावरण संरक्षण की एक नई मिसाल पेश की है, जिसका बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ की बिजली परियोजनाओं से निकलने वाले कचरे को खपाने में काम आ रहा है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न परियोजनाओं में वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 2.17 करोड़ मीट्रिक टन और वर्ष 2025-26 में 62 लाख मीट्रिक टन से अधिक फ्लाई-ऐश को सड़क निर्माण में खपाया गया, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक लगभग 20 लाख मीट्रिक टन फ्लाई-ऐश का उपयोग किया जा चुका है। इतना ही नहीं, स्टील उद्योग के अपशिष्ट यानी स्लैग, अनुपयोगी टायरों के रबर और बायो-बिटुमेन जैसी वैकल्पिक सामग्रियों को रिसायकल कर वर्ष 2024-25 में 30,477 मीट्रिक टन तथा वर्ष 2025-26 में 2691 मीट्रिक टन सामग्रियों का उपयोग करके ग्रीन-हाइवे की परिकल्पना को साकार किया गया है।

जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के प्रयास

सड़क निर्माण के साथ-साथ जल संरक्षण और भूजल संवर्धन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर सुधर सके। छत्तीसगढ़ के राजमार्गों के आस-पास के ग्रामीण अंचलों सहित देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 13 अमृत सरोवरों का जीर्णोद्धार और निर्माण किया गया है। वर्षा जल संचयन को गति देने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स की संख्या को वर्ष 2024-25 में 14 से बढ़ाकर अगले ही वर्ष 105 कर दिया गया। निर्माण कार्यों और पौधों की सिंचाई में पीने योग्य साफ पानी की बर्बादी रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्राप्त 323 किलोलीटर शोधित जल का उपयोग किया गया, जो जल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

संवेदनशील वनों में इको-फ्रेंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर

वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए एनएचएआई ने छत्तीसगढ़ की विभिन्न परियोजनाओं में बेहद संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों में अत्याधुनिक इको-फ्रेंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। छत्तीसगढ़ के सीतानदी-उदंती अभ्यारण्य के संवेदनशील क्षेत्र में करीब 3 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक सुरंग इसका नायाब उदाहरण है। इस निर्माण से वाहनों का आवागमन भूमिगत होगा और जंगल के शांत माहौल पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र में विशेष ध्वनि-अवरोधक (साउंड बैरियर्स) लगाए जा रहे हैं, ताकि वन्य जीव और पक्षी वाहनों के शोर से विचलित न हों। साथ ही, पेड़ों पर रहने वाले जीवों के लिए सड़क के ऊपर मंकी-कैनोपी और हाथियों व अन्य वन्य जीवों के बेरोकटोक विचरण के लिए विशेष एलिफेंट-पास एवं एनिमल-अंडर विकसित किए जा रहे हैं।

बी-कॉरिडोर और मेडिसीन पार्क से स्थानीय समृद्धि

हाइवे को एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने छत्तीसगढ़ के मैदानी और वनांचल मार्गों के किनारों पर एनएचएआई द्वारा कई अनोखे प्रयोग किए जा रहे हैं। सड़कों के किनारे विशेष बी-कॉरिडोर (मधुमक्खी गलियारा) विकसित किया जाएगा, जिससे आसपास के खेतों में प्राकृतिक परागण बढ़ेगा और स्थानीय किसानों की फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। वहीं, बंजर और खाली पड़ी जमीनों पर मेडिसीन पार्क (औषधि वन) तैयार कर नीम, तुलसी, एलोवेरा और आंवला जैसे हजारों औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही, एनएचएआई ने "एक पेड़ माँ के नाम 2.0" अभियान के अंतर्गत बीते वर्ष छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे और डिवाइडर्स पर ढाई लाख से अधिक पौधों का रोपण कर हरित राजमार्ग का एक नया कीर्तिमान रचा है।

हरित भारत संकल्प.... एक पेड़ मां के नाम योजना से राज्य हुआ हरियाली से आच्छादित

छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण एवं पौधा वितरण का नया महा-अभियान

धनंजय राठौर
संयुक्त संचालक
अशोक कुमार चंद्रवंशी
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को सुदृढ़ करना आधुनिक युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही पर्यावरण-हितैषी नीतियों के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर साफ दिखने लगे हैं। देश में हरित आवरण (ग्रीन कवर) को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम मनरेगा और नगर वन योजना जैसी शासकीय योजनाओं के बेहतर समन्वय से हर साल वृक्षारोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है।

इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन संवर्धन और हरियाली को बढ़ाने के लिए विगत वर्षों से लगातार वृहद पैमाने पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाया जा रहा है। आज 05 जून 2026 को विश्व वानिकी दिवस के पावन अवसर पर इस वर्ष के भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है।

भारत सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा चालू वर्ष (वर्षाऋतु 2026) के लिए राज्य को 2 करोड़ 50 लाख पौधों के रोपण एवं वितरण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त हुआ है। राज्य शासन ने इस लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल करने के लिए सभी वनमंडलों में व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस पूरे अभियान को सितंबर 2026 तक पूर्ण कर प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार के 'मेरी लाईफ' पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।

विभागीय योजनाएं इसके तहत 2,124 हेक्टेयर क्षेत्र और 12.70 किलोमीटर में 20 लाख 72 हजार पौधों का रोपण किया जाएगा।

मनरेगा अंतर्गत- ग्रामीण विकास के समन्वय से 6 किलोमीटर के क्षेत्र में 2,400 पौधों का रोपण होगा।

कैम्पा (CAMPA) मद- वन विकास के तहत 4,376 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में 42 लाख 18 हजार पौधों का रोपण सुनिश्चित किया गया है।

अन्य योजनाएं- विभिन्न विकास कार्यों के साथ 92 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 लाख 38 हजार पौधों का रोपण किया जाएगा।

कुल रोपण क्षेत्र- इस प्रकार राज्य के कुल 6,592 हेक्टेयर क्षेत्र और 22.90 किलोमीटर की पट्टी में 64 लाख 31 हजार पौधों का रोपण कार्य संपन्न होगा।

निःशुल्क हरित वितरण

आम जनमानस की सहभागिता के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 74 लाख 45 हजार पौधों का वितरण कर राज्य को हरितिमा से सराबोर किया जाएगा।

किसान वृक्ष मित्र योजना

कृषकों की आय बढ़ाने और निजी सहभागिता के लिए प्रदेश के किसानों की निजी भूमियों पर 17,670 एकड़ रकबा में 1 करोड़ 20 लाख 47 हजार पौधों का रोपण किया जाएगा।

कुल उपलब्धि का लक्ष्य- इन सभी शासकीय और निजी प्रयासों को मिलाकर इस वर्ष प्रदेश में कुल 259.23 लाख (लगभग 2.59 करोड़) पौधों के रोपण एवं वितरण का गौरवशाली लक्ष्य निर्धारित है।

बीते वर्ष 2025 की वर्षाऋतु में छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्यों से कहीं आगे बढ़कर पौधे लगाने और उनके वितरण में रिकॉर्ड सफलता हासिल की थी।

लक्ष्य से दोगुनी प्राप्ति

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 1 करोड़ 65 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध विभाग ने राज्य में रिकॉर्ड 3 करोड़ 55 लाख 45 हजार पौधों का रोपण एवं वितरण कर उसे 'मेरी लाईफ' पोर्टल पर अपलोड किया था।

योजनावार कुल रोपण कुल 13,030 हेक्टेयर और 14.50 किलोमीटर क्षेत्र में 1 करोड़ 67 लाख 78 हजार पौधों का रोपण किया गया। इसमें विभागीय योजनाएं (26.21 लाख), मनरेगा (11,941), कैम्पा (18.49 लाख), अन्य योजनाएं (67.92 लाख) और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (55 लाख) का सराहनीय योगदान रहा।

बढ़ती विषमता का आईना

आय कर रिटर्न्स से उभरा रुझान साफ है। भारत में प्रत्यक्ष कर राजस्व अधिक से अधिक धनी वर्गों पर निर्भर होता जा रहा है। वैसे, विषमता बढ़ने की पुष्टि हवाई यात्रा संबंधी ताजा आंकड़ों से भी हुई है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दाखिल हुए आयकर रिटर्न्स से देश में बढ़ रही आर्थिक गैर-बराबरी की झलक मिली है। एक अंग्रेजी वित्तीय अखबार के विश्लेषण के मुताबिक पांच लाख रुपये तक आमदनी वाले व्यक्तियों के रिटर्न की संख्या 2024-25 की तुलना में गिर कर लगभग आधी रह गई है। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ कि गुजरे वित्त वर्ष में सरकार के आय कर दरों में बढ़ोतरी करने की वजह से बहुत से लोगों के लिए रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता नहीं रह गई। मगर इससे यह भी जाहिर होता है कि लोगों के क्रमिक रूप से ऊपर के आय वर्ग में शामिल होने का क्रम टूटा हुआ है।

2019-20 के बाद से 2022-25 तक पांच लाख से कम आबादी वाले वर्ग की ओर से सबसे ज्यादा रिटर्न फाइल होते थे। मगर अब पांच से दस लाख रुपये के बीच की आमदनी वाले समूह ने यह स्थान हासिल कर लिया है। 2024-25 में इस आय वर्ग में चार करोड़ 75 लाख रिटर्न फाइल हुए थे, जो पिछले वर्ष पांच करोड़ 45 लाख तक पहुंच गए। रुझान साफ है। भारत में प्रत्यक्ष कर राजस्व अधिक से अधिक धनी वर्गों पर निर्भर होता जा रहा है।

महात्मा गांधी नरेगा से जल संरक्षण का महाअभियान, रोजगार और आजीविका को मिली नई ताकत

जलवायु परिवर्तन और बढ़ते जल संकट के बीच छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़कर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत किया है। 24 अप्रैल 2025 से प्रारंभ 'मोर गांव-मोर पानी' महाअभियान के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा के तहत प्रदेशभर में जल संरक्षण, रोजगार सृजन और आजीविका संवर्धन को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत लगभग 1610 करोड़ रुपये की लागत से एक लाख से अधिक जल संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। इन कार्यों से जहां जल सुरक्षा मजबूत हो रही है, वहीं प्रदेश में प्रतिदिन 11 लाख से अधिक ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है, जिनमें 57 प्रतिशत महिलाएं हैं। जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का यह संगम छत्तीसगढ़ को सतत ग्रामीण विकास की दिशा में नई पहचान दे रहा है।

जल संरक्षण से आजीविका का सृजन

राज्य सरकार ने जल संरक्षण को सीधे आजीविका से जोड़ते हुए कई अभिनव पहलें शुरू की हैं। वर्तमान में समाज के संवेदनशील एवं कमजोर वर्गों की निजी भूमियों पर 13,065 आजीविका डबरियों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इन परिसंपत्तियों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को मत्स्य पालन, बागवानी और अन्य आयवर्धक गतिविधियों से जोड़कर अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

नवा तरिया–आय के जरिया' के अंतर्गत विकसित हो रहे 624 सामुदायिक तालाब

इसी प्रकार 'नवा तरिया-आय के जरिया' पहल के अंतर्गत 624 सामुदायिक तालाब विकसित किए जा रहे हैं। क्लस्टर स्तर पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को इन जल संरचनाओं से जोड़कर स्थायी आजीविका के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इससे जल संरक्षण केवल प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तक सीमित न रहकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम भी बन रहा है।

इसके साथ साथ अन्य जल सरंक्षण, संवर्धन कार्य भी व्यापक सामुदायिक भागीदारी से किए जा रहे है। प्रधान मंत्री आवास ग्रामीण अंतर्गत निर्मित 1.50 लाख से अधिक आवास में हितग्राहियों द्वारा अपने खर्च पर स्वेच्छा से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है ।

तकनीक से जल संरक्षण को मिली नई दिशा

'मोर गांव-मोर पानी' अभियान की विशेषता यह है कि इसमें आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। जल संरक्षण कार्यों की वैज्ञानिक योजना और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए GIS आधारित युक्तधारा प्लानिंग, CLART एप के माध्यम से स्थल चयन तथा वाटरशेड सिद्धांतों का उपयोग किया जा रहा है। भू-जल स्तर की नियमित निगरानी के लिए जलदूत प्रणाली लागू की गई है, जिसके माध्यम से खुले कुओं के जल स्तर का मापन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत भवनों की दीवारों पर भू-जल स्तर का लेखन कर स्थानीय स्तर पर जल बजट तैयार करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिससे जल प्रबंधन अधिक प्रभावी और समुदाय आधारित बन सके।

पारदर्शिता का अभिनव मॉडल

मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश ने तकनीक आधारित नवाचारों को अपनाया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्यूआर कोड प्रदर्शित किए गए हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण अपने गांव में स्वीकृत एवं पूर्ण कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही रोजगार दिवस, आवास दिवस, सामाजिक अंकेक्षण और जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से योजना में पारदर्शिता एवं जनविश्वास को और सुदृढ़ किया गया है। अभियान की सबसे बड़ी सफलता इसमें समाज के सभी वर्गों की सहभागिता है। जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, सामाजिक संगठनों, गैर-सरकारी संस्थाओं और ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी से जल संरक्षण का यह अभियान जनआंदोलन का रूप ले चुका है। व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रमों, ग्राम सभाओं और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण को लोगों के दैनिक व्यवहार का हिस्सा बनाने का प्रयास किया गया है।

मनरेगा अंतर्गत प्रदेश में प्रतिदिन 11 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार, 57 प्रतिशत महिलाएं

1610 करोड़ रुपये से एक लाख से अधिक जल संरक्षण कार्यों का निर्माण

जल संरक्षण, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, तकनीकी नवाचार का अभिनव मॉडल

छत्तीसगढ़ का 'मोर गांव-मोर पानी' अभियान आज 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास' की अवधारणा को धरातल पर साकार करता दिखाई दे रहा है। जल संरक्षण, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, तकनीकी नवाचार, पारदर्शिता और अभिसरण का यह मॉडल राज्य को भागीदारी से साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि का नया अध्याय लिख रहा है।

रेल यात्रियों के हित में बैंगलुरू जाने के लिए विशेष ट्रेन की सुविधा

ब्यूरोचीफ संतोष साहू

भाटापारा। रेलवे प्रशासन द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बिलासपुर यलहंका बेंगलुरु बिलासपुर के मध्य यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये 05-05 फेरे के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। उक्त ट्रेन संख्या 08261 बिलासपुर- यलहंका समर स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से प्रत्येक बुधवार को 03 जून 2026 से 01 जुलाई 2026 तक चलेगी इसी तरह ट्रेन संख्या 08262 यलहंका बेंगलुरु बिलासपुर समर स्पेशल ट्रेन यलहंका से प्रत्येक गुरुवार को 04 जून 2026 से 02 जुलाई 2026 तक चलेगी। इस ट्रेन में 02 एसएलआरडी, 04 सामान्य, 10 स्लीपर, 04 एसी- कोच सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। गाड़ी संख्या 08261 बिलासपुर- यलहंका बेंगलुरु समर स्पेशल ट्रेन 03 जून 2026 से 01 जुलाई 2026 तक प्रत्येक बुधवार को बिलासपुर से 14.00 बजे रवाना होगी तथा भाटापारा आगमन 14.40 बजे, प्रस्थान 14.42 बजे, रायपुर आगमन 15.35 बजे, प्रस्थान 15.40 बजे, दुर्ग आगमन 16.25 बजे, प्रस्थान 16.30 बजे, राजनादगाँव आगमन 16.49 बजे, प्रस्थान 16.51 बजे, डोंगरगढ़ आगमन 17.12 बजे, प्रस्थान 17.14 बजे, गोंदिया आगमन 18.15 बजे, प्रस्थान 18.25 बजे, वडसा आगमन 19.32 बजे, प्रस्थान 19.34 बजे, चांदाफोर्ट आगमन 21.18 बजे, प्रस्थान 21.20 बजे, बल्लारशाह आगमन 22.05 बजे, प्रस्थान 22.15 बजे, सिरपुर कागजनगर आगमन 22.59 बजे, प्रस्थान 23.00 बजे, मंचिर्याल आगमन 23.54 बजे, प्रस्थान 23.55 बजे, दूसरे दिन काजीपेट आगमन 01.38 बजे, प्रस्थान 01.40 बजे, चर्लपल्ली आगमन 03.08 बजे, प्रस्थान 03.10 बजे, सिकंदराबाद आगमन 05.55 बजे, प्रस्थान 06.05 बजे, लिंगमपल्ली 06.18 बजे, प्रस्थान 06.20 बजे, विकाराबाद आगमन 07.03 बजे, प्रस्थान 07.05 बजे, तांडूर आगमन 07.43 बजे, प्रस्थान 07.45 बजे, यादगीर आगमन 09.13 बजे, प्रस्थान 09.15 बजे, कृष्णा जंक्शन आगमन 09.50 बजे, प्रस्थान 10.00 बजे, रायचूर आगमन 10.28 बजे, प्रस्थान 10.30 बजे, मंत्रालयम रोड आगमन 10.53 बजे, प्रस्थान 10.55 बजे, गुंटकल आगमन 12.25 बजे, प्रस्थान 12.35 बजे, गुत्ती आगमन 13.03 बजे, प्रस्थान 13.05 बजे, अनंतपुर आगमन 13.23 बजे, प्रस्थान 13.25 बजे, धर्मवरम आगमन 15.30 बजे, प्रस्थान 15.35 बजे, हिंदूपुर आगमन 16.38 बजे, प्रस्थान 16.40 बजे तथा 19.00 बजे यलहंका स्टेशन पहुंचेगी।

इसी तरह ट्रेन संख्या 08262 यलहंका बेंगलुरु -बिलासपुर समर स्पेशल ट्रेन 04 जून 2026 से 02 जुलाई 2026 तक प्रत्येक गुरुवार को यलहंका से 21.30 बजे रवाना होगी तथा हिंदूपुर आगमन 22.38 बजे, प्रस्थान 22.40 बजे, दूसरे दिन धर्मवरम आगमन 00.55 बजे, प्रस्थान 01.00 बजे, अनंतपुर आगमन 01.28 बजे, प्रस्थान 01.30 बजे, गुत्ती आगमन 02.18 बजे, प्रस्थान 02.20 बजे, गुंटकल आगमन 03.35 बजे, प्रस्थान 03.40 बजे, मंत्रालयम रोड आगमन 04.58 बजे, प्रस्थान 05.00 बजे, रायचूर आगमन 05.40 बजे, 05.42 बजे, कृष्णा जंक्शन आगमन 06.10 बजे , प्रस्थान 06.20 बजे, यादगीर आगमन 06.48 बजे, प्रस्थान 06.50 बजे, तांडूर आगमन 08.39 बजे, प्रस्थान 08.40 बजे, विकाराबाद आगमन 09.18 बजे, प्रस्थान 09.20 बजे, लिंगमपल्ली आगमन 10.03 बजे, प्रस्थान 10.05 बजे, सिकंदराबाद आगमन 10.55 बजे, प्रस्थान 11.05 बजे, चर्लपल्ली आगमन 11.33 बजे, प्रस्थान 11.35 बजे, काजीपेट आगमन 13.23 बजे, प्रस्थान 13.25 बजे, मंचिर्याल आगमन 14.48 बजे, प्रस्थान 14.50 बजे, सिरपुर कागजनगर आगमन 15.33 बजे, प्रस्थान 15.35 बजे, बल्लारशाह आगमन 17.35 बजे, प्रस्थान 17.45 बजे, चांदाफोर्ट आगमन 18.15 बजे, प्रस्थान 18.17 बजे, वडसा आगमन 19.48 बजे, प्रस्थान 19.50 बजे, गोंदिया आगमन 21.50 बजे, प्रस्थान 22.00 बजे, डोंगरगढ़ आगमन 22.58 बजे, प्रस्थान 23.00 बजे, राजनादगाँव आगमन 23.25 बजे, प्रस्थान 23.27 बजे, तीसरे दिन दुर्ग आगमन 00.20 बजे, प्रस्थान 00.25 बजे, रायपुर आगमन 01.05 बजे, प्रस्थान 01.10 बजे, भाटापारा आगमन 02.05 बजे, प्रस्थान 02.07 बजे तथा 03.30 बजे बिलासपुर स्टेशन पहुंचेगी

संक्षिप्त समाचार

पात्रता अनुसार बनाए जा रहे हैं हितग्राहियों के राशन कार्ड

भाटापारा। राज्य शासम के निदेर्शानुसार कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग द्वारा पात्रता अनुसार हितग्राहियों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान मिरगी से संलग्न ग्राम खैरी आर जनपद पंचायत भाटापारा में कुल 490 राशन कार्ड धारी है जिसमे अंत्योदय कार्ड धारी परिवार 38 , निराश्रित कार्ड धारी परिवार 4,प्राथमिकता कार्ड धारी परिवार 402,सामान्य राशन कार्ड धारी परिवार 46 है।इस प्रकार इस ग्राम के 90 प्रतिशत परिवार शासन के निःशुल्क खाद्यान्न योजना का लाभ उठा रहे है।वर्तमान में संचानालय खाद्य नागरिक आपूर्ति अवम् उपज़ेक्ता संरक्षण द्वारा एपीएल राशन कार्ड को कैंसिल कर बीपीएल कार्ड नहीं बनाये जाने का निर्देश है। जैसे ही शासन से बीपीएल राशन कार्ड बनाने का निर्देश प्राप्त होगा वैसे ही ग्राम पंचायत खैरी आर के ग्रामीणों का पात्रता परीक्षण संबंधित ग्राम के पटवारी , सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भाटापारा से कराकर नवीन राशन कार्ड जारी करने की कार्यवाही की जाएगी।

समग्र शिक्षा में शत्रुहन डहरिया के कार्यों की प्रदेश स्तर पर प्रशंसा

भाटापारा। परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा द्वारा शिक्षकों के मध्य अकादमिक संवाद एवं नवाचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले 12 वर्षों से प्रकाशित किए जा रहे चर्चा पत्र के जून 2026 अंक-1 में शासकीय प्राथमिक शाला लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के प्रधान पाठक शत्रुहन कुमार डहरिया के कार्यों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। चर्चा पत्र के एजेंडा-8 सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप यह रेखांकित किया गया है कि जब घर, शाला और समुदाय मिलकर कार्य करते हैं, तब विद्यार्थियों का सीखना और उनका भविष्य दोनों सशक्त होते हैं। इसी संदर्भ में शत्रुहन डहरिया द्वारा विद्यालय को केवल शिक्षण केंद्र न बनाकर समुदाय से जुड़ा एक सरि य एवं प्रेरणादायी शिक्षण परिसर बनाने के प्रयासों को सराहा गया है। चर्चा पत्र में उल्लेखित है कि डहरिया ने

जनसहयोग एवं सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से विगत तीन वर्षों में लगभग 12.50 लाख रुपये मूल्य के संसाधन विद्यालय विकास हेतु जुटाए हैं। इन संसाधनों के सहयोग से विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, आधारभूत सुविधाओं तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को नई दिशा मिली है। उक्त उल्लेखनीय उपलब्धि पर शिक्षक एवं प्रधान पाठक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ शिक्षक साथियों, मित्रों, संकुल समन्वयकों, संकुल प्राचार्यों एवं शिक्षा जगत से जुड़े अनेक लोगों ने डहरिया को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। सभी ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनके कार्य प्रदेश के अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की नई मिसाल स्थापित करेंगे।

भाटापारा में नालंदा परिसर के लिए 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत

भाटापारा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी भाटापारा नगर पालिका क्षेत्र में 250 सीटर नालंदा परिसर ,लाईब्रेरी व अध्ययन केन्द्र निर्माण के लिए 441.49 लाख रुपएं की राशि की स्वीकृति दी है। जिससे शहर व क्षेत्र के छात्र छात्राओं और प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को अध्ययन के लिए सर्व सुविधा युक्त आधुनिक एवं शांत वातावरण वाला केन्द्र नालंदा परिसर के रूप में प्राप्त हो सकेगा। उक्त आधुनिक लाईब्रेरी की स्वीकृति पर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव , वित्त मंत्री ओपी चौधरी , क्षेत्रिय सासंद बृजमोहन अग्रवाल व वरिष्ठ भाजपा नेता शिवरतन शर्मा के प्रति आभार प्रकट किया है। इधर नगरीय क्षेत्र में नालंदा परिसर के लिए शासन द्वारा स्वीकृति मिलने पर नगर व क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता राकेश तिवारी , सुनिल यदु, गोलु यदु ,सुनिल शर्मा , हेमंत नायडु , सतीश तलरेजा , मनीष मिश्रा, पवन वर्मा , डब्ल्यु सिंग ठाकुर , संकेत अग्रवाल , मथुरा यदु , योगेश अनंत , दिलीप छाबड़िया , लक्ष्मीकांत टंडन सहित अन्य लोगो ने खुशी प्रकट करते हुए शिवरतन शर्मा व अश्वनी शर्मा के प्रति आभार प्रकट किया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय दिनेश सेन को दी श्रद्धांजलि

शोक संतप्त परिवार से की मुलाकात

वैशाली नगर विधायक श्री रिकेश सेन के निवास पहुंचकर व्यक्त की गहरी संवेदना, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने दुर्ग प्रवास के दौरान आज भिलाई स्थित लोकांगन परिसर पहुंचकर वैशाली नगर विधायक श्री रिकेश सेन के बड़े भाई स्वर्गीय श्री दिनेश सेन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय श्री सेन के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर विधायक श्री रिकेश सेन एवं शोक संतप्त परिजनों से आत्मीय मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और इस कठिन समय में परिवार को धैर्य एवं संबल प्रदान करने की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी प्रियजन का वियोग जीवन की ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं हो सकती। उन्होंने स्वर्गीय श्री दिनेश सेन के निधन को परिवार एवं समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। इस अवसर पर विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, विधायक श्री ईश्वर साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा गणमान्यजन उपस्थित थे।

सेमरिया घाट में शिवनाथ नदी का जल प्रवाह सुखने से लोग परेशान

ब्यूरोचीफ संतोष साहू

भाटापारा। शहर से 7 किलोमीटर दुर उत्तर दिशा में बहने वाली शिवनाथ नदी भीषण गर्मी व जगह जगह नदी के पानी का औद्योगिक प्रयोग के कारण जून माह के शुरूआती दिन में एक लंबी अवधि के बाद पहली बार सेमरिया घाट में नदी पुरी तरह सुख गई है।

पिछले 50 वर्षो में यह पहला अवसर है जब सेमरिया घाट पर बनाये गये एनिकट से पानी आगे नही बढ़कर पुरी तरह सेमरिया घाट क्षेत्र में सुख गई है। नदी के सुख जाने से लोग परेशान है पेयजल के साथ साथ दैनिक उपयोग में लोगो को परेशानियों से जुझना पड़ रहा है। जहां लोग बड़ी तादाद में गर्मी के दौरान सुकुन के दो पल बिताने सेमरिया घाट पहुंचते थे उन्हें भी निराशा हाथ लगी है क्योकि सेमरिया घाट शिवनाथ नदी पुरी तरह सुख चुकी है। वहां पर एक बुंद भी पानी नही होने से जनसामान्य के साथ साथ पशु पक्षी वन जीव जंतु के अलावा सेमरिया घाट नदी क्षेत्र में नाव चलाकर पानी से अपनी आजिविका चलाने वाले केवट व मछली पकड़ने वालो ं को बिना पानी के नाव चलाने में हो रही दिक्कत के चलते नाव को सेमरिया घाट क्षेत्र से पुरी तरह बाहर निकालना पड़ गया है। शिवनाथ नदी में पानी नही होने से लगभग एक दर्जन से अधिक नाविक बेरोजगार हो गये है। किसी समय शिवनाथ नदी की धार इतनी अधिक प्रबल होती थी कि भीषण गर्मी में भी लोग सेमरिया घाट पहुंचकर नदी स्नान का लाभ प्राप्त करते थे। लेकिन इतनी भयावह रूप से नदी के सुख जाने पर सभी आश्चर्य चकित प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे है। लोगो की मान्यता है कि शिवनाथ नदी के संपूर्ण हिस्से को संरक्षित व संवर्धित करने ध्यान नही दिया गया तो आने वाले वर्षो में भाटापारा क्षेत्र गंभीर जल संकट से जुझेगा क्योकि सन् 1959 से शिवनाथ नदी का जल शहर वासियों को पेयजल आपूर्ति कर रहा है। इस दिशा में शासन प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है की आखिर शिवनाथ नदी का प्रवाह क्यो टुट गया जबकि बारो महीने सेमरिया घाट क्षेत्र में नदी में पूर्व में जल प्रवाह रहता था।

सभी यात्री ट्रेन यथावत चलेगी, रेल प्रशासन ने तमाम ट्रेनों को रिस्टोर किया

भाटापारा। दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे द्वारा रेल अधोसंरचना के विकास एवं परिचालन क्षमता में वृद्धि के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते बिलासपुर रेलवे जंक्शन एवं झारसुगड़ा रेलवे जंक्शन के बीच चांपा रेलवे स्टेशन में चौथी रेल लाईन का काम तथा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य जो कि आगामी 7 जून से 19 जून तक प्रस्तावित था जिसके कारण अनेक रेल यात्री ट्रेन को रद्द करने के अलावा कुछ के मार्ग परिवर्तन करके चलाने तथा कुछ एक को आधे रास्ते तक चलाने का पूर्व में निर्णय लिया गया था। मौजुदा समय में रेल यात्रियों की बढती भीड़ एवं उनकी रेल यात्रा की सुविधा का ख्याल करते हुए तथा उनकी यात्रा को सुगम बनाये रखने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने उपरोक्त नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को आगामी आदेश तक स्थगित करने का निर्णय लिया है परिणाम स्वरूप उक्त कार्य के कारण पूर्व में 7 जून से 19 जून 2026 तक रद्द की गई सभी रेलयात्री ट्रेन एवं सभी एक्सप्रेस व लोकल ट्रेनों को रिस्टोर किया गया है। जिसके चलते अब सभी ट्रेने अपने निर्धारित मार्ग निर्धारित तिथि ,समय पर सामान्य रूप से चलेगी। रेल प्रशासन ने रेल यात्रियों को होने वाली असुविधा को न्युनतम रखने तथा सुरक्षित के साथ साथ बेहतर रेल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है व निरंतर प्रयास है कि अधिक से अधिक सुविधाए रेल यात्रियों को प्राप्त हो। उक्त संबंध में रेल प्रशासन ने सभी रेल यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व समस्त प्रकार की जानकारी रेलवे के अधिकृत पूछताछ केन्द्र से लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ करें।

रबी धान की आवक बढने के साथ ही बारदाना बाजार में आया उछाल

ब्यूरोचीफ संतोष साहू

भाटापारा। क्षेत्र में रबी सीजन का धान अब तेजी से बिक्री के लिए पहुंचने लगा है जिसके कारण पोहा मिल संचालको ं को पर्याप्त मात्रा में धान मिलने लगा है। धान की आवक बढ़ने के साथ ही इसके बिक्री रेट में लगातार गिरावट होने लगा है। वही अब भाटापारा का उत्पादित अच्छा पोहा भी मात्र 40 रूपयें प्रति किलों में सहज रूप से मिलने लगा है इस बीच धान के अलावा शासन द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के चलते दाल दलहन , तिलहन की पैदावार चना , गेंहू, मटर , सरसों , बटरी , व अन्य उत्पादन को प्रोत्साहन देने के कारण उपरोक्त सभी जिंसों की भी आवक बढ़ गई है जिसके चलते भाटापारा नगर में स्थित तीन दर्जन से अधिक छोटे बड़े सभी बारदाना दुकानों में भारी ग्राहकी का सैलाब उमड़ पड़ा है। उपरोक्त सभी बारदाना दुकानों में मध्यम रेट वाले बारदाना की मांग जबरदस्त निकल पड़ी है जिससे बारदाना बाजार ग्राहकी से उछाल मार रहा है। रबी सीजन के धान को भरने के लिए ज्यादातर किसान , ब्रोकर्स , मिलर्स व कोचियें 15 रूपयें से लेकर 16 रूपयें प्रति नग वाले जुट कट्टा बड़ी तादाद में खरीद रहे है जिसके कारण बारदाना दुकान में जुट कट्टा की भारी मांग उठने से दिन रात मजदुर व रेजा बोरा सिलाई के काम में जुटे हुये है इसी तरह चावल , खण्डा , कनकी भरने के लिए भी प्लास्टिक बोरी की जबरदस्त मांग बनी हुई है और वह लोगो को सहज रूप से 5 रूपयें प्रति नग में उपलब्ध हो रहा है। बारदाना दुकान में कम रेट वाले जुट कट्टा व प्लास्टिक बोरी की मांग से जहां बारदाना सिलने वाले मजदुरों को भरपुर काम मिल रहा है वहीं रायपुर, दुर्ग , बिलासपुर , रायगढ़ की तुलना में भाटापारा शहर में कम रेट में बारदाना मिलने के कारण दुसरे क्षेत्र कसडोल कटगी, पवनी, बिलाईगढ़ ,सारंगगढ़ , सरसिवा , धंरसिवा , सरगांव , पथरिया , मारो , बैतलपुर , बिल्हा, दामाखेड़ा , मुंगेली , तखतपुर ,दामापुर , कवर्धा , दाढ़ी , संबलपुर , बेमेतरा , थान खम्हरिया ,बेरला, धमधा, चकरभाठा , बोदरी, लवन , लाहोद , तुरमा , अहिल्दा , कोयदा , अमेरा , ज़ैंसा , संडी , रोहांसी , खरतोरा , हथबंद , रिंगनी, तिल्दा , सिमगा ,राका , घुरसेना , टेमरी सहित अन्य क्षेत्र के लोग भारी संख्या में कम रेट का बारदाना खरीदने भाटापारा पहूंच रहे है। बारदाना जगत में अच्छी ग्राहकी का माहौल आने वाले 15 जून तक और रहने की संभावना है इस बीच बढती पेट्रोल डीजल की कीमत से परिवहन भाड़ा व गैरेज किराया बढने से बोरा की लागत बढ़ जाने के कारण बरदाना व्यापारियों के फायदे में भी भारी मांग के बावजुद कमी आ गई है। फलस्वरूप वे ज्यादा प्रसन्न नही है उन्हें भी महंगाई ने परेशान कर रखा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने बदली तकदीर

चित्ररेखा निषाद के जीवन में अपना पक्का मकान होने का सपना हुआ साकार

ब्यूरोचीफ अनिल सिंघानिया

बेमेतरा। कहते हैं कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती और अगर सही समय पर सरकारी योजनाओं का साथ मिल जाए, तो अभावों का जीवन भी खुशहाली की नई इबारत लिख सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जिला बेमेतरा , विकासखंड नवगढ़ के ग्राम बैहरसरी के रहने वाली चित्ररेखा निषाद ने। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने उनके जीवन में उम्मीदों की नई रोशनी बिखेर दी है और अब उनका अपना पक्का मकान होने का वर्षों पुराना सपना हकीकत बन चुका है। बताना चाहेंगे कि सुशासन तिहार के अंतर्गत गत दिवस ग्राम पंचायत बैहरसाकेरी में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने अपने कर कमलों से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान पूर्ण होने पर घर की चाबी सौंप कर उन्हें गृह प्रवेश की शुभकामनाएं दी है।

अभावों के साये में बीता जीवन

चित्ररेखा निषाद के लिए जीवन कभी भी आसान नहीं रहा। कच्ची दीवारों और जर्जर छत के नीचे गुजारा करना उनके लिए दैनिक संघर्ष का हिस्सा था। बरसात के दिनों में टपकती छत और सुरक्षा की चिंता उनके मन में हमेशा बनी रहती थी। एक स्वाभिमानी महिला होने के बावजूद आर्थिक तंगी के कारण पक्का घर बनाना उनके लिए एक दूर का सपना जैसा था।

योजना बनी सहारा

सरकार की लोक-कल्याणकारी योजना 'प्रधानमंत्री आवास योजना' उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आई। पात्रता की शर्तों को पूरा करने के बाद, जब चित्ररेखा का चयन इस योजना के तहत हुआ, तो उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। योजना के तहत मिली सहायता राशि ने न केवल उनके हौसले बुलंद किए, बल्कि पक्के मकान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

अब सपनों का घर है अपना

आज चित्ररेखा निषाद का पक्का मकान बनकर तैयार है। यह सिर्फ ईंट-पत्थर की चारदीवारी नहीं है, बल्कि यह उस आत्मसम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है, जिसे उन्होंने वर्षों से संजोया था। अपने घर में प्रवेश करते हुए चित्ररेखा भावुक होकर कहती हैं, "प्रधानमंत्री आवास योजना ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी है। पहले जहाँ बारिश में सोने की चिंता सताती थी, आज उसी छत के नीचे मैं और मेरा परिवार सुरक्षित और चैन से रहते हैं। मुझे पक्के घर का सपना पूरा करने में सरकार का बड़ा सहयोग मिला है।"

महिला सशक्तिकरण का उदाहरण

चित्ररेखा निषाद की यह कहानी न केवल एक पक्के मकान के मिलने की खुशी है, बल्कि यह सरकार की उन योजनाओं की सफलता का प्रमाण भी है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही हैं। उनकी यह उपलब्धि क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है, जो अपने परिवार की खुशहाली और बेहतर जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने साबित कर दिया है कि जब सरकारी मंशा साफ हो और लाभार्थियों तक सही समय पर सहायता पहुंचे, तो कैसे एक गरीब परिवार का जीवन पूरी तरह बदला जा सकता है।

संक्षिप्त समाचार

भाजपा सोशल मीडिया थानखम्हरिया मंडल कार्यकारिणी की घोषणा

थानखम्हरिया। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया विभाग द्वारा संगठन विस्तार के तहत थानखम्हरिया मंडल की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। यह घोषणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश प्रभारी भाजपा सोशल मीडिया मितुल कोठारी, जिला प्रभारी हर्षिता पाण्डेय, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय साहू तथा थानखम्हरिया मंडल अध्यक्ष केशव पटेल की सहमति से जिला प्रभारी भाजपा सोशल मीडिया पं. अंकुश तिवारी द्वारा की गई।

श्री पारस नाथ योगी जी

श्री गणेश वर्मा जी

घोषित कार्यकारिणी में पारसनाथ योगी (गोपालपुर) को मंडल संयोजक तथा श्रीमती मन्त्रोरा यादव (खम्हरिया) को सहसंयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं ओम पाल (बरगा), सोनू शर्मा (टिपनी) एवं भार्गव लोधी (तोरण) को सदस्य बनाया गया है।

जिला प्रभारी भाजपा सोशल मीडिया पं. अंकुश तिवारी ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सोशल मीडिया संगठन और जनता के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम है। नई कार्यकारिणी पार्टी की नीतियों, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा संगठनात्मक गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारियां संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगी। पार्टी नेतृत्व ने सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों से सरि यता और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया है।

थानखम्हरिया में 7 जून से श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन

ब्यूरो चीफ – अनिल सिंघानिया

थानखम्हरिया। नगर के रामचंद्र रामरतन धर्मशाला में 7 जून से 15 जून 2026 तक संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर नगरवासियों में उत्साह का माहौल है तथा तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

आयोजकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कथा का शुभारंभ 7 जून को भव्य कलश यात्रा, वेदी पूजन एवं गौरी-गणेश पूजन के साथ होगा। कथा का वाचन कथा व्यास पंडित अक्षय नारायण जी महाराज (थानखम्हरिया) द्वारा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से किया जाएगा। सप्ताह भर चलने वाली कथा में परीक्षित जन्म, ध्रुव चरित्र, प्रह्लाद चरित्र, गजेन्द्र मोक्ष, वामन अवतार, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र एवं गीता उपदेश सहित विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। समापन 15 जून को हवन, पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण के साथ होगा।

आयोजक समिति ने नगर एवं क्षेत्र के श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा श्रवण कर धर्म लाभ लेने की अपील की है। कार्यक्रम का आयोजन वार्ड क्रमांक 2 एवं 3 के रहवासियों तथा समस्त नगरवासियों के सहयोग से किया जा रहा है।

खाद दुकानों पर कृषि विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई

नियमों के उल्लंघन पर दुकानें सील कर दिया नोटिस

रायपुर, आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कोरबा जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा सहकारी एवं निजी उर्वरक दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त खाद-बीज उपलब्ध कराने, किसी भी प्रकार की कालाबाजारी और अनियमितता रोकने जिला प्रशासन द्वारा ये कार्यवाही की जा रही है। कृषि विभाग के उप संचालक डी.पी.एस. कंवर ने बताया कि खरीफ सीजन 2026 के लिए विभाग ने विशेष सतर्कता अपनाई है। 29 मई को 18 दुकानों की जांच की गई, जिनमें 6 दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। एक दुकान पर विर य प्रतिबंध लगाया गया एवं सिद्धी विनायक ट्रेड्स, सिरली (पाली) से 56 बोरी यूरिया जप्त की गई। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से अब तक कोरबा जिले के 115 सहकारी एवं निजी उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा चुका है। अनियमितता पाए जाने पर 28 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा 5 निजी दुकानों पर 21 दिनों के लिए विर य प्रतिबंध लगाया गया है। सिरली (पाली) स्थित सिद्धी विनायक ट्रेड्स से अवैध रूप से भंडारित 56 बोरी यूरिया की जप्ती की गई। कोरबा जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे खाद खरीदते समय दुकानदार से पक्का बिल अवश्य प्राप्त करें। यदि कोई दुकानदार निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलता है या बिल देने से मना करता है, तो इसकी शिकायत तुरंत संबंधित विकासखंड कृषि अधिकारी या जिला स्तर के कंट्रोल रूम में दर्ज कराएं। किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने उर्वरक दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण एवं कठोर निगरानी अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा।

सियासत में सादगी का अनोखा अध्याय

सामूहिक विवाह सम्मेलन में विधायक दीपेश साहू ने रचाया विवाह

बेमेतरा/रायपुर। राजनीति में जहां अक्सर भव्यता, प्रोटोकॉल और वीआईपी संस्कृति की चर्चा होती है, वहीं बेमेतरा में रविवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सादगी, संस्कार और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव स्वयं बैलगाड़ी के सारथी बने और बेमेतरा विधायक दीपेश साहू की बारात की लगाम संभालते नजर आए। यह अनूठा दृश्य देखते ही देखते पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया।

मौका था बेमेतरा में आयोजित सामूहिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन का, जहां विधायक दीपेश साहू ने भी इसी मंच से विवाह संस्कार संपन्न करने का निर्णय लिया। आमतौर पर जनप्रतिनिधियों के विवाह समारोह भव्य आयोजनों और बड़ी व्यवस्थाओं के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन विधायक दीपेश साहू ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को चुनकर सादगी और सामाजिक समानता का संदेश देने का प्रयास किया।

विवाह समारोह के दौरान जब दूल्हे के रूप में विधायक दीपेश साहू बैलगाड़ी में सवार होकर बारात लेकर निकले तो सबसे खास बात यह रही कि बैलगाड़ी की कमान स्वयं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संभाली। ग्रामीण परिवेश और भारतीय परंपराओं की झलक लिए यह दृश्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। रास्ते भर मौजूद लोगों ने तालियों और शुभकामनाओं के साथ बारात का स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक मौजूद रहे। लोगों ने इसे जनप्रतिनिधियों द्वारा समाज को सकारात्मक संदेश देने वाला कदम बताया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर विधायक दीपेश साहू ने यह संदेश दिया कि विवाह जैसे पवित्र संस्कार का महत्व दिखावे और खर्च से कहीं अधिक सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक संस्कारों में निहित है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव का सारथी बनकर बारात में शामिल होना भी लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा।

राजनीतिक पद और प्रोटोकॉल से ऊपर उठकर उन्होंने जिस सहजता के साथ इस आयोजन में भागीदारी निभाई, उसे उपस्थित लोगों ने सादगी और आत्मीयता का प्रतीक बताया।

आवास योजना-जिलों को 2677 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी

रायपुर। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन को नई गति मिली है। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों को 2677.15 करोड़ रुपए की केंद्रीय एवं राज्यांश राशि जारी की गई है। यह राशि एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से जिलों को आवंटित की गई है, ताकि पात्र हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जा सकें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि"हर गरीब को पक्का घर" का संकल्प छत्तीसगढ़ में तेजी से साकार हो रहा है। राज्य में प्रतिदिन 1600 से अधिक पक्के आवासों का निर्माण किया जा रहा है तथा विगत ढाई वर्षों में 10.60 लाख से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही 6 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों गरीब परिवारों के सपनों, आत्मसम्मान और सुरक्षित जीवन की कहानी है। साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी राशि का उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करते हुए पात्र हितग्राहियों के आवास शीघ्र पूर्ण कराए जाएं, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को समय पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में महिला स्व-सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

9.45 लाख रुपये के गांजा के साथ दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

नरेन्द्र कुमार सेन

गरियाबंद। 9.45 लाख रुपये के गांजा के साथ दो अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार, अमलीपदर पुलिस की कार्यवाही जिले में अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमलीपदर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 18.900 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजा की कीमत 9 लाख 45 हजार रुपये आंकी गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 3 जून 2026 को थाना प्रभारी अमलीपदर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति एक सिल्वर रंग की हीरो एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल (क्रमांक सीजी-04-एलयू-2550) में भारी मात्रा में गांजा लेकर ओडिशा से अमलीपदर क्षेत्र की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम को तत्काल ग्राम बिरीघाट के पास रवाना किया गया और मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए और वाहन के आधार पर संदिग्धों को रोका गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम हीरालाल केवर्त (29 वर्ष) और टीकम टोलटिया (36 वर्ष) निवासी ग्राम मोहरा, थाना चांदाहांडी, जिला नवरंगपुर (ओडिशा) बताया। तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से 18.900 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 9.45 लाख रुपये है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।

जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 9.89 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

16वें उर्स पाक समारोह में कव्वाल जुनैद सुल्तानी ने बांधा समां

थान खम्हरिया। थान खम्हरिया में एकता उर्स पाक कमेटी द्वारा आयोजित 16वें उर्स पाक समारोह में प्रसिद्ध कव्वाल जुनैद सुल्तानी (बदायूं, उत्तर प्रदेश) ने अपनी शानदार प्रस्तुति से उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक चली कव्वाली में लोगों ने सूफियाना कलाम का भरपूर आनंद लिया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य अन्नपूर्णा रामगोपाल चंद्राकर उपस्थित रहीं। विशेष रूप से विरेन्द्र सिन्हा (अध्यक्ष, एकता उर्स पाक कमेटी), राजेश ठाकुर (संरक्षक), करीम बेग (पार्षद), इदरीस बेग, सत्यम अग्रवाल, संदीप वर्मा, सुनील वर्मा, बाबा अशरफ, मिर्जा असलम एवं रहीस बेग उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षक हरि केड़िया ने किया। इस अवसर पर कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि एकता उर्स पाक कमेटी ने अपने सफल आयोजन के 16 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जो क्षेत्र में आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है।

कार्यक्रम को सफल बनाने में शेख वसीम, जाहिद, सफीक, आसिफ, सिद्दीक, शोएब, वलिम, आतिफ अली, एजाज शेख, नईम खान, शेख अनस खान सहित कमेटी के सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आयोजन में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे का जन्मदिन मनाया

ब्यूरोचीफ अनिल सिंघानिया

थानखम्हरिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविन्द्र चौबे का जन्मदिन नगर सहित विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कांग्रेस कार्यालय साजा में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया तथा उनके दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

इस अवसर पर खमरिया ब्लॉक अध्यक्ष रोशन सिन्हा ने पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे के जनसेवा एवं राजनीतिक योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका नेतृत्व कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने ईश्वर से रविन्द्र चौबे के स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की प्रार्थना करते हुए जनसेवा में निरंतर सक्रिय रहने की कामना की।

कार्यकर्ताओं ने रविन्द्र चौबे को विकास पुरुष एवं कुशल प्रशासक बताते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की। कार्यर म में मनहरण सिन्हा, जितेन्द्र उपाध्याय, सतीष जोशी, गौरव बिंदल, हुकुम सिन्हा, विरेन्द्र सिन्हा पार्षद, हनी परिहार, शरद देवांगन, चंद्रशेखर तिवारी, नरेश पाटिल, दुर्गेश पात्रे, शिवसागर सिन्हा, गणेश मंडावी, सोमनाथ सिन्हा, टेकराम साहू, महेश निषाद, गणेश मांडवी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सुशासन तिहार 2026

संवेदनशील पहल से समस्याओं का त्वरित समाधान

जनसमस्या निवारण शिविर बना आमजन के लिए राहत का माध्यम, मोहनलाल को मिला तत्काल लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार आयोजित सुशासन तिहार 2026 के तहत जनसमस्या निवारण शिविर आम नागरिकों के लिए भरोसे और राहत का सशक्त माध्यम बनते जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से शासन की योजनाओं और सेवाओं को सीधे गांव-गांव तक पहुंचाते हुए समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत सरखों में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याओं एवं मांगों से जुड़े आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर रहे हैं। शिविर में ग्राम बनारी निवासी मोहनलाल अपनी समस्या लेकर पहुंचे। उन्होंने किसान किताब से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया, जो उनके कृषि कार्यों के लिए आवश्यक था। आवेदन प्राप्त होते ही राजस्व विभाग के अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की और मौके पर ही उन्हें नई किसान किताब प्रदान कर दी। समस्या का तत्काल समाधान मिलने से श्री मोहनलाल के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि इस पहल से उनकी समस्या कुछ ही समय में हल हो गई। उन्होंने जनसमस्या निवारण शिविर को जनहितकारी पहल बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

सुशासन तिहार

सरोधी की चौपाल में दिखी बदलाव की कहानी

महतारी वंदन योजना से सशक्त हुई केकती बाई की जिंदगी

रायपुर। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का ग्राम सरोधी में आयोजित चौपाल कार्यक्र म केवल प्रशासनिक संवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आम जनजीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जीवंत तस्वीर भी बन गया। इसी चौपाल में सामने आई एक ऐसी कहानी, जिसने सरकारी योजनाओं के वास्तविक प्रभाव को भावनात्मक रूप से उजागर किया। ग्राम सरोधी की निवासी श्रीमती केकती मरावी, अपने पति राजेंद्र मेरावी और तीन बच्चों-चिरंजीव, किरण और विक्र ांत के साथ एक साधारण किसान परिवार से जुड़ी हैं। खेती-किसानी ही उनके जीवन का मुख्य आधार है, लेकिन सीमित आय के बीच परिवार का खर्च चलाना हमेशा एक चुनौती रहा है।

केकती बाई बताती हैं कि महतारी वंदन योजना ने उनके जीवन में नई रोशनी लाई है। अब तक उन्हें योजना की 26 किश्तें मिल चुकी हैं, जिससे वे घर के छोटे-छोटे खर्चों में हाथ बंटा पा रही हैं। पहले जहां हर छोटी जरूरत के लिए सोच-विचार करना पड़ता था, वहीं अब उनके पास आत्मनिर्भरता का एक आधार बन गया है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों से वे "स्वच्छता दीदी" के रूप में भी कार्य कर रही हैं, जिससे उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस सिलेंडर मिलने से उनके परिवार के स्वास्थ्य में भी सुधार आया है और रसोई का काम आसान हुआ है।

केकती बाई केवल अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि वे "जय मां बंजारी महिला स्व सहायता समूह" की अध्यक्ष भी हैं। समूह के माध्यम से उन्हें 15 हजार रुपए का अनुदान मिला है, जिससे वे अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। भावुक होते हुए केकती बाई ने कहा कि आज उनका परिवार पहले से कहीं अधिक सशक्त और आत्मविश्वासी महसूस करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं ने उनके जीवन को नई दिशा दी है। ग्राम सरोधी की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब योजनाएं सही हितग्राहियों तक पहुंचती हैं, तो वे केवल आर्थिक मदद नहीं देतीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की नई राह भी खोलती हैं।

सुशासन तिहार : भरोसे, पारदर्शिता और जनभागीदारी का उत्सव

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रशासन पहुँचा जनता के द्वार

दुर्ग/छत्तीसगढ़। प्रदेश में मनाया जा रहा "सुशासन तिहार" अब केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि आम नागरिकों के विश्वास और प्रशासनिक जवाबदेही का सशक्त माध्यम बन चुका है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के उद्देश्य से जिस व्यापक जनसंपर्क और समाधान आधारित व्यवस्था को लागू किया है, उसका सकारात्मक प्रभाव अब गाँव-गाँव और शहर-शहर दिखाई देने लगा है। सुशासन तिहार के माध्यम से शासन और जनता के बीच की दूरी कम हुई है। वर्षों से लंबित समस्याओं के निराकरण, योजनाओं की पारदर्शी मॉनिटरिंग, शिकायतों के त्वरित समाधान और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान प्रभावी साबित हो रहा है।

प्रशासनिक व्यवस्था में दिखाई दे रहा बदलाव ..

पहले जहाँ आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब शिविर आधारित व्यवस्था के माध्यम से अधिकारी स्वयं जनता तक पहुँच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व, पेयजल, सड़क, बिजली, राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, आवास एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है।

सुशासन तिहार के दौरान लगाए जा रहे समाधान शिविरों में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएँ लेकर पहुँच रहे हैं और त्वरित कार्रवाई से संतुष्टि भी व्यक्त कर रहे हैं। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और संवेदनशीलता दोनों बढ़ी हैं।

"सरकार जनता के साथ" का संदेश ..

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि शासन का वास्तविक उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। इसी सोच के अनुरूप अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम, चौपाल, जनसंवाद और निरीक्षण कार्यक्र मों के माध्यम से सीधे नागरिकों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस पहल ने आम नागरिकों में यह विश्वास मजबूत किया है कि उनकी समस्याएँ अब केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उनका समाधान प्राथमिकता के साथ किया जाएगा।

तकनीक और पारदर्शिता का बढ़ा उपयोग ..

सुशासन तिहार में डिजिटल मॉनिटरिंग और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली को भी प्रभावी ढंग से जोड़ा गया है। शिकायतों की एंट्री, ट्रैकिंग और समयबद्ध निराकरण से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आई है। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और कार्यों की जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिली है।

प्रदेश के कई जिलों में अधिकारियों द्वारा फील्ड विजिट कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया जा रहा है। स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल और राशन दुकानों की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण कर सुधारात्मक निर्देश दिए जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस ...

सुशासन तिहार के दौरान ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। पेयजल संकट, सड़क मरम्मत, सिंचाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

कई स्थानों पर वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिससे किसानों और ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं महिला स्व-सहायता समूहों, युवाओं और किसानों को स्वरोजगार एवं सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

जनता की भागीदारी से मजबूत हो रहा लोकतंत्र

विशेषज्ञों का मानना है कि सुशासन तिहार केवल प्रशासनिक आयोजन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सहभागिता का सशक्त उदाहरण है। जनता सीधे अधिकारियों से संवाद कर रही है और शासन की कार्यप्रणाली में सक्रि य भागीदारी निभा रही है। इस अभियान ने यह साबित किया है कि यदि प्रशासन संवेदनशीलता, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ कार्य करे तो आम नागरिकों का विश्वास स्वत: मजबूत होता है।

सकारात्मक संदेश के साथ आगे बढ़ता छत्तीसगढ़ ...

सुशासन तिहार ने प्रदेश में एक सकारात्मक प्रशासनिक संस्कृति विकसित करने की दिशा में नई शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार का फोकस केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि धरातल पर परिणाम देने पर दिखाई दे रहा है। जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान, योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग और प्रशासनिक जवाबदेही का यह मॉडल आने वाले समय में सुशासन की नई पहचान बन सकता है।

सुशासन तिहार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पीएम जनमन के हितग्राही को सौंपी खुशियों की चाबी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत जारी राज्यव्यापी दौरे में आज खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के छुईखदान विकासखंड के ग्राम सरोधी में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सुभान सिंह मेरावी को उनके नवनिर्मित आवास की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया। सुभान सिंह ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री स्वयं उनके गांव आकर उन्हें यह सौभाग्य देंगे। उनके लिए यह केवल घर नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास का प्रतीक है।बउन्होंने बताया कि उन्हें वन अधिकार पट्टा के तहत 3 एकड़ 2 डिसमिल भूमि मिली है, जिस पर खेती कर वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। साथ ही उनकी पत्नी को महतारी वंदन योजना के तहत नियमित आर्थिक सहायता भी मिल रही है, जिससे घरेलू जरूरतों में सहयोग मिल रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि शासन का लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

सुशासन की मोटरसाइकिल से दुर्गम पहाड़ों तक पहुँचे कलेक्टर-एसपी

गोंडेरास और नीलावाया में ऐतिहासिक सुशासन चौपाल

सुकमा। छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन तिहार 2026 अभियान के तहत अब विकास की किरण केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे सुदूर वनांचलों तक पहुँच रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता की एक नई मिसाल पेश की। बुधवार को कलेक्टर अमित कुमार और पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने किसी प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए, खुद मोटरसाइकिल चलाकर 30 किलोमीटर लंबे उबड़-खाबड़ और दुर्गम रास्तों को पार किया और पहुंचविहीन ग्राम गोंडेरास व नीलावाया पहुँचे। जिला प्रशासन सुशासन तिहार के माध्यम से 31 व्यक्तिगत योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं को सीधे ग्रामीणों के द्वार तक पहुँचा रहा है। कलेक्टर और एसपी का यह दौरा साबित करता है कि जब प्रशासन संवेदनशीलता के साथ दूरी मिटाता है, तो जनता के मन में व्यवस्था के प्रति विश्वास और बदलाव की नई उम्मीद जागती है।

ग्राम गोंडेरास में इमली की छाँव में समस्याओं का तत्काल समाधान

गोंडेरास गांव में कलेक्टर और एसपी ने किसी आलीशान मंच के बजाय इमली के पेड़ के नीचे बिछी खाट पर बैठकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। ग्रामीणों द्वारा सोलर प्लेट्स के खराब होने की शिकायत पर कलेक्टर ने तत्काल क्रेडा विभाग को सभी घरों में मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गाँव में आंगनबाड़ी और पंचायत भवन जैसे बुनियादी कार्यों के लिए 70 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को ही सौंपी गई है। शिविर में 17 किसान क्रेडिट कार्ड, 12 जाति प्रमाण पत्र और 11 पीएम-किसान प्रकरणों का निराकरण, 2 किसान किताब, 2 पटवारी प्रतिवेदन सहित कई दस्तावेज मौके पर ही वितरित किए गए।

स्वास्थ्य सुरक्षा और पुलिया की सौगात

ग्राम नीलावाया पहुँचकर अधिकारियों ने जमीन पर बैठकर चौपाल लगाई। बारिश के दिनों में ग्रामीणों को होने वाली 15 किमी की अतिरिक्त दूरी को खत्म करने के लिए कलेक्टर ने मौके पर ही नाले पर पुलिया निर्माण की स्वीकृति दी। 4 मोतियाबिंद मरीजों को जिला अस्पताल भेजने और गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए सचिव को कड़े निर्देश दिए गए। शिविर के दौरान 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म पूरी की गई और 22 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र तत्काल बनाकर सौंपे गए।

कागजी नहीं, धरातली सुशासन हमारा लक्ष्य

कलेक्टर अमित कुमार ने ग्रामीणों से कहा कि शासन का लक्ष्य नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गाँव) योजना के जरिए हर घर को बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के सैचुरेशन (पूर्णता) से जोड़ना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय पंचायत को निर्माण एजेंसी बनाना कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने का एक बड़ा कदम है। यह पहली बार है जब कोई कलेक्टर हमारे गाँव तक मोटरसाइकिल से पहुँचा है। अब हमें भरोसा है कि हमारी समस्याएँ अनसुनी नहीं रहेंगी। गांव के सरपंच श्री जोगा वंजामी ने अधिकारियों के आगमन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह पहली बार है जब कोई कलेक्टर उनके गांव तक पहुंचा है।

नागरिकों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता -मंत्री दयालदास

जन-समस्याओं का हुआ त्वरित निराकरण, बैहरसरी में आयोजित समाधान शिविर में उमड़ा जनसैलाब

ब्यूरोचीफ अनिल सिंघानिया

बेमेतरा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल की अगुवाई में विकासखंड नवागढ़ के ग्राम पंचायत बैहरसरी में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं एवं मांगें प्रशासन के समक्ष रखीं, जिनमें से अनेक प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें तरक्की के अवसर उपलब्ध कराना शासन की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकास की किरण समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही सरकार का संकल्प है। मंत्री श्री बघेल ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

समावेशी विकास और जनकल्याण पर विशेष जोर

मंत्री श्री दयालदास बघेल ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार, किसानों की आय वृद्धि तथा कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे योजनाओं के क्रि यान्वयन की नियमित निगरानी करें, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके और शासन की योजनाओं का प्रभाव सीधे नागरिकों तक पहुंचे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आम जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने तथा प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा केवल योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि उन योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाना है।

ग्रामवासियों की मांग पर तालाब में पथरी निर्माण हेतु 6 लाख रुपये की घोषणा

जन-सुनवाई में समस्याएं सुनीं, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

समाधान शिविर के दौरान मंत्री श्री बघेल ने स्वयं ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, आवास, पेयजल, सड़क, पेंशन तथा विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कई प्रकरणों का निराकरण मौके पर ही किया गया, जिससे ग्रामीणों ने संतोष व्यक्त किया।

जन-सेवा को मिली प्राथमिकता, विभिन्न योजनाओं से हितग्राही हुए लाभान्वित

शिविर में ग्रामवासियों की मांग पर तालाब में पथरी निर्माण कार्य हेतु 6 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से नागरिकों को शासन की योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया गया। शिविर में 3 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 हितग्राहियों को ऋण पुस्तिका, 6 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 4 हितग्राहियों को निक्षय पोषण किट तथा 7 बालिकाओं को नोनी सुरक्षा योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजना से लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त अनेक नागरिकों को विभिन्न प्रमाण-पत्र, पंजीयन एवं अन्य सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया गया।

शासन और जनता के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बने समाधान शिविर

समाधान शिविरों के माध्यम से शासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है। ग्रामीणों को अपनी समस्याएं रखने के लिए एक प्रभावी मंच मिल रहा है, वहीं प्रशासन को भी जमीनी स्तर की आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रि यान्वयन तथा पारदर्शी प्रशासन को नई मजबूती मिल रही है।

विभागीय स्टॉलों में मिली योजनाओं की विस्तृत जानकारी

शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों में नागरिकों को सरकारी योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रि या तथा मिलने वाले लाभों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक आवेदन भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हेमा दिवाकर, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री अजय साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्र म का वातावरण जनसहभागिता, जनसेवा और विकास के संकल्प से ओतप्रोत रहा।

गरियाबंद विकासखंड के आमदी(द) में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित

नरेन्द्र कुमार सेन

गरियाबंद / राज्य शासन द्वारा संचालित सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गरियाबंद विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला परिसर आमदी(द) में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सम्मिलित 10 गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर अपनी समस्याओं, शिकायतों एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर में कुल 619 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष आवेदनों को समय-सीमा में निराकरण के लिए संबंधित विभागों को सौंपा गया।

इस दौरान जनपद सभापति गणेशाराम ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार योजनाओं का मेला और जनकल्याण का पर्व है। शासन द्वारा योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य सराहनीय है। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर आमजन की समस्याओं, शिकायतों एवं मांगों का समाधान किया जा रहा है। अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की, ताकि मूलभूत सुविधाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सके।

10 गॉवों के नागरिकों ने सौंपे 619 आवेदन

क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सुरेंद्र सोनटेके ने कहा कि सुशासन तिहार आम जनता के लिए समाधान का उत्सव है। इसके माध्यम से अधिकारी-कर्मचारी गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं तथा शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में कई पात्र हितग्राही योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, लेकिन सुशासन तिहार के माध्यम से ऐसे लोगों को योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है तथा महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। साथ ही पोर्टल पुनः खुलने पर नए हितग्राहियों का पंजीयन भी किया जाएगा। सरकार द्वारा गांव-गांव तक सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

कलेक्टर बीएस उइके के मार्गदर्शन में शिविर में शामिल अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे ने कहा कि शिविर में प्राप्त सभी शिकायतों, मांगों एवं समस्याओं का गंभीरतापूर्वक निराकरण किया जाएगा। शासन स्तर से संबंधित मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्च स्तर पर भेजा किया जाएगा और उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि खाद एवं बीज का वितरण शासन के नियमानुसार सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। जिन गांवों में नेटवर्क की समस्या है, वहां अधिकारी स्वयं पहुंचकर परमिट जारी करेंगे, जिससे त्वरित खाद का वितरण किया जा सकेगा। शिविर के दौरान दो हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की चाबी प्रदान की गई। चार महिलाओं की गोद भराई की गई तथा बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छह विद्यार्थियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा तीन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया गया।

इस दौरान एसडीएम हितेश्वरी बाघे तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पाण्डेय ने आमदी में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध शौचालय, मॉड्यूलर किचन, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, पूर्ण विद्युतीकरण तथा गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए उपलब्ध उपकरणों की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं की सराहना की।

15 दिनों से नहीं पहुंच रही मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की बस, मरीज परेशान

ब्यूरोचीफ अनिल सिंघानिया

थानखम्हरिया। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य बस विगत लगभग 15 दिनों से नगर में नहीं पहुंच रही है। इससे गरीब, जरूरतमंद एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित यह बस वर्षों से लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। बस में स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श एवं आवश्यक दवाइयों का वितरण किया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलता रहा है। पिछले दो सप्ताह से बस के नहीं आने के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों और चिकित्सकों के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

ग्रामीणों एवं नगरवासियों ने शासन-प्रशासन से स्वास्थ्य बस की सेवा शीघ्र प्रारंभ कराने की मांग की है। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इस योजना पर काफी हद तक निर्भर हैं। इस संबंध में डॉ. विनय शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य बस में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण उसे मरम्मत के लिए रायपुर भेजा गया है। बस का मेंटेनेंस कार्य चल रहा है और आगामी दो दिनों में इसे पुनः संचालित कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य बस के बंद रहने से निःशुल्क इलाज और दवा सुविधा से वंचित लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।

युवा मोर्चा परपोड़ी मंडल कार्यकारिणी का विस्तार, विधायक ईश्वर साहू से की सौजन्य भेंट

ब्यूरोचीफ अनिल सिंघानिया

थानखम्हरिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा परपोड़ी मंडल की नई कार्यकारिणी के विस्तार के उपरांत मंडल अध्यक्ष नीलू साहू के नेतृत्व में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने साजा विधायक ईश्वर साहू से उनके निवास पहुंचकर सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने विधायक को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।

विधायक ईश्वर साहू ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन की मजबूती एवं युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा संगठन की रीढ़ है और युवाओं की ऊर्जा एवं समर्पण से संगठन को नई दिशा मिलती है।

इस दौरान युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने संगठनात्मक गतिविधियों एवं आगामी कार्यक्र मों को लेकर विधायक से चर्चा की तथा संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्र म में युवा मोर्चा के विभिन्न पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) रामकृष्ण साहू के निर्देशन पर बेमेतरा पुलिस की अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्यवाही जारी

बेमेतरा। पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव, एसडीओपी बेमेतरा श्री भूषण एक्का, एसडीओपी बेरला श्री विनय कुमार के मार्गदर्शन में बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थों, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी क्रम में 02 जून 2026 को थाना खम्हरिया पुलिस टीम द्वारा 03 वाहन में DJ बांध कर बिना अनुमति के DJ बजाते पाये जाने पर DJ सामान जप्त कर अनावेदक जय निषाद, रामजी ठाकुर, जितेन्द्र मुलचंद के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई हैं।

02 जून 2026 को थानखम्हरिया में 19:00 बजे नगर भ्रमण दौरान जुलुस के साथ अनावेदक वाहन कमांक सीजी 07 सीएच- 0940 के चालक जय निषाद पिता स्व. सागर सिंह निषाद उम्र 39 वर्ष निवासी दुर्ग पोलसाय पारा थाना दुर्ग जिला दुर्ग, वाहन कमांक सीजी 07 सीटी.3749 का चालक रामजी ठाकुर पिता दुर्गाराम ठाकुर उम्र 31 वर्ष निवासी शंकर नगर दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग, वाहन कमांक एम.एच.31एफ.सी.8624 का चालक जितेन्द्र मुलचंद बंसोर पिता मूलचंद बंसोर उम्र 52 वर्ष निवासी नागपुर मानवता नगर थाना गिट्टी खदान जिला नागपुर महाराष्ट्र द्वारा उक्त तीनों वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रो से चोंगा, बेस एम्प्लीफायर को तेज आवाज में रात्रि 10:00 बजे के बाद भी ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग कर रहे थे जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अवहेलना करने एवं उक्त अनावेदकों को DJ बजाने की अनुमति के संबंध जानकारी लेने पर अनुमति नहीं होना पाया गया। अनावेदकों का कृत्य धारा 15(1) कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन करना पाये जाने एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन कमांक सीजी 07 सीएच- 0940, वाहन कमांक सीजी 07 सीटी. 3749, वाहन कमांक एम.एच.31 एफ.सी.8624 मे ध्वनि विस्तारक यंत्रो से चोंगा, बेस एम्प्लीफायर एवं वाहन के दस्तावेज तथा अनावेदकों ड्रायविंग लाइसेंस जप्त कर विधिवत वैधानिक कार्यवाही की गई हैं। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना थानखम्हरिया निरीक्षक चन्द्रदेव वर्मा, उप.निरीक्षक ओंकार प्रसाद साहू, प्रधान आरक्षक अजय कुमार सहित थाना थानखम्हरिया के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।

बिना अनुमति DJ तेज आवाज में बजाते पाए जाने पर कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही

ड्रोन से लेकर जैविक खेती तक, कृषि के हर नवाचार को बढ़ावा दे रही है सरकार-मुख्यमंत्री

ड्रोन तकनीक, नैनो उर्वरक, जैविक खेती और फसल विविधीकरण से कृषि को मिल रही नई दिशा

रायपुर। आधुनिक तकनीकों, नवाचारों और किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और सम्मानजनक बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित 'मुख्यमंत्री किसान संवाद' में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों के साथ आत्मीय चर्चा करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने खेती-किसानी से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए तथा किसानों के प्रश्नों और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और कम उम्र में ही खेती-किसानी तथा परिवार की जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिला। इसी कारण वे किसानों की जरूरतों, चुनौतियों और उनके संघर्ष को निकटता से समझते हैं। उन्होंने कहा कि पहले खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं का अभाव था, लेकिन आज कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए हैं। मशीनों, वैज्ञानिक पद्धतियों और नई तकनीकों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है तथा किसानों के लिए नई संभावनाएं खुली हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं तथा कृषि यंत्रीकरण जैसी योजनाओं ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान गांवों में किसानों से सीधे संवाद के दौरान यह अनुभव हुआ है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के चेहरे पर दिखाई देने वाला आत्मविश्वास ही सरकार की योजनाओं की वास्तविक सफलता है। कार्यक्रम में शामिल ड्रोन दीदियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव कम समय, कम लागत और अधिक प्रभावशीलता के साथ किया जा सकता है। इससे खेती आधुनिक, वैज्ञानिक और लाभकारी बन रही है तथा महिलाओं के लिए भी रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और जैविक खेती को भविष्य की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इनके उपयोग से लागत कम होती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है तथा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है।

नैनो उर्वरकों के उपयोग से खेती बनेगी अधिक लाभकारी और टिकाऊ : कम लागत, बेहतर उत्पादन और स्वस्थ मिट्टी का माध्यम है नैनो उर्वरक - मुख्यमंत्री

'मुख्यमंत्री किसान संवाद' कार्यक्रम में किसानों से किया आत्मीय संवाद

उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को अपनाने का आह्वान किया। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद और उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आगामी खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों ने अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, मौसंबी, पपीता और आम जैसी फसलों की उन्नत खेती के अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल विविधीकरण किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है तथा बदलते समय के अनुरूप किसानों को परंपरागत खेती के साथ-साथ बागवानी, प्राकृतिक कृषि, जैविक खेती और अन्य नवाचारों को अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज का युवा खेती को केवल परंपरा नहीं बल्कि आधुनिक उद्यम के रूप में देख रहा है। यह परिवर्तन कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत सकारात्मक है। राज्य सरकार कृषि आधारित कौशल विकास, ड्रोन संचालन, कृषि मशीनरी, जैविक खेती और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वे नई तकनीकों और नवाचारों को अपनाने में संकोच न करें। समय के साथ बदलती तकनीकों को अपनाकर सीमित लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचार, वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तकनीक ही किसानों की समृद्धि का आधार बनेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बयान की चर्चा तेज, प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल

ब्यूरो चीफ अनिल सिंघानिया

थानखम्हरिया – मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा दिए गए वक्तव्य के बाद राजनीतिक और संगठनात्मक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है।

कार्यक्रम में उनके संबोधन को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रतिरि याएं सामने आ रही हैं। कई लोगों ने इसे जनभावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाला वक्तव्य बताते हुए उनकी स्पष्टवादिता की सराहना की है।

वहीं दूसरी ओर, हाल के दिनों में विभिन्न शासकीय आयोजनों में प्रशासनिक व्यवस्था और मंचीय प्राथमिकताओं को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं एवं नेताओं का मानना है कि कई कार्यक्रमों में जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को अत्यधिक प्रमुखता दी जा रही है, जबकि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं को अपेक्षित सम्मान एवं स्थान नहीं मिल पा रहा है।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम के मंच संचालन और प्राथमिकताओं को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी

कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं तथा दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उनका मानना है कि जनप्रतिनिधि जनता के सीधे प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए शासकीय कार्यक्रमों में उनकी गरिमा और भूमिका के अनुरूप सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संगठन से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि यदि शासन, प्रशासन और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित नहीं किया गया तथा मंचीय व्यवस्थाओं में संतुलन नहीं बनाया गया, तो इसका प्रभाव भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी पड़ सकता है।

कार्यकर्ताओं ने सरकार और संगठन के शीर्ष नेतृत्व से इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है, ताकि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान हो और शासन-प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया निरीक्षण

दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता-मुख्यमंत्री साय

रायपुर। जहां कभी दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां विकास की राह में चुनौती बनती थीं, वहां आज आधुनिक अधोसंरचना नए अवसरों के द्वार खोल रही है। प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम कोण्डापल्ली पहुंचकर बीजापुर-पूर्वती मार्ग पर निर्मित बेली ब्रिज का निरीक्षण किया।

उन्होंने पुल की निर्माण तकनीक, उपयोगिता और क्षेत्र के विकास में उसकी भूमिका की जानकारी लेते हुए इसे बदलते बस्तर की नई तस्वीर का प्रतीक बताया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाएं केवल निर्माण कार्य नहीं हैं, बल्कि वे दूरस्थ क्षेत्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाले मजबूत माध्यम हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक हो।

कम समय, कम लागत और अधिक मजबूती की तकनीक

भारतीय सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा निर्मित यह बेली ब्रिज बीजापुर-पूर्वती सड़क परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बेली ब्रिज पारंपरिक पुलों की तुलना में अधिक किफायती, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनका निर्माण सामान्य पुलों की अपेक्षा लगभग पांच गुना कम लागत में किया जा सकता है तथा इन्हें मात्र एक माह के भीतर तैयार किया जा सकता है। दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए यह तकनीक अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है।

बीजापुर में 21 बेली ब्रिज बने विकास के वाहक

उल्लेखनीय है कि बीजापुर जिले में अब तक 21 बेली ब्रिजों का निर्माण किया जा चुका है। इन पुलों के निर्माण से दूरस्थ गांवों तक आवागमन सुगम हुआ है तथा लोगों को आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच में बड़ी राहत मिली है। इन संरचनाओं ने क्षेत्र में विकास और जनसेवाओं के विस्तार को नई गति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के श्रमिक और युवा ही विकास यात्रा के वास्तविक निर्माणकर्ता हैं। उन्होंने श्रमिकों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके अनुभव भी साझा किए।

बदलते बस्तर की नई पहचान

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर में अधोसंरचना विकास के माध्यम से नई संभावनाओं का निर्माण हो रहा है। कोण्डापल्ली का यह बेली ब्रिज केवल एक पुल नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और सुशासन का सशक्त प्रतीक है। यह उस नए बस्तर की पहचान है, जहां विकास अब दूरस्थ गांवों और दुर्गम अंचलों तक मजबूती से पहुंच रहा है तथा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी : नारायण भूषणिया द्वारा डीबी कार्प लिमिटेड प्लाट नंबर-40/44 इंडस्ट्रीयल एरिया बीरगांव उरला रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कराकर एच.डी.डी./49, फेस-2 मेन रोड, कबीर नगर रायपुर से प्रकाशित, संपादक-नारायण भूषणिया मो.नं. 09300491602, RNI पंजीयन क्रमांक: CHHHIN/2010/34778, Email ID- krantirath.cg@gmail.com, / web- www.krantirath.com